कोटद्वार, शुक्रवार
6 फरवरी 2026
वर्षः 48
अंकः 254 पृष्ठः 4
मूल्यः 2.00

जयन्त

निर्भीक – निष्पक्ष – जनसरोकार

www.dainikjayantnews.com
स्थापित 1979
संस्थापक : स्व. नगेन्द्र उनियाल

डाक पंजीयन पी.ए.ओ.07-2024-26 फोनः 9412081969 email: nagendra.uniyal@gmail.com

एक नजर

दिन दहाड़े लाखों की चोरी

देहरादून। छत पर कपड़े सूखाने गई महिला के घर में दिन दहाड़े चोरी हो गई। घर के प्रवेश गेट की कुंडी लगी थी। चोरों ने उसे खोलकर वारदात को अंजाम दिया। बीते 20 जनवरी को हुई घटना में पीड़ति को लंबे चक्कर कटाने के बाद बुधवार को शहर कोतवाली पुलिस ने केस दर्ज किया है। नेताजी मोहल्ला निवासी सुशील कुमार गुप्ता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि चोरी की यह घटना बीते 20 जनवरी की दोपहर को हुई। उस वक्त उनकी पत्नी सपना गुप्ता घर पर अकेली थीं। दोपहर करीब दो बजे वह नीचे के दरवाजे पर कुंडा लगाकर छत पर कपड़े सुखाने चली गईं। करीब आधे घंटे बाद नीचे आईं, तो कमरे का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे में रखी अलमारी का ताला टूटा हुआ था। सारा सामान फर्श पर बिखरा पड़ा था। चोर सोने की तीन अंगूठी, चांदी की तीन जोड़ी पायल, करीब 30 सिक्के, एक जोड़ी डामंड टाप्स और 2100 रुपये नगदी चुराकर ले गए। घटना के तुरंत बाद पीड़ित ने पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना दी। जिसके बाद चीता पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आस–पास के इलाके में छानबीन की। उस वक्त कोई संदिग्ध हाथ नहीं लगा। तब पीड़ति को झांसा दिया कि जल्द खुलासा कर दिया गया। लंबे समय तक कोई कार्रवाई न होने पर पीड़ति पुलिस अफसरों तक पहुंचे। एसपी सिटी स्वप्निल मुयाल ने बताया कि बुधवार को पीड़ति की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

कार की टक्कर से स्कूटर सवार की मौत

देहरादून। डालनवाला क्षेत्र में तेज रफ्तार कार की टक्कर से स्कूटर सवार पेट्रोप पंप कर्मचारी की मौत हो गई। घटना के एक महीने बाद मामले में केस दर्ज कराया गया है। इंस्पेक्टर डालनवाला संतोष कुंवर ने बताया कि हर्रावाला निवासी प्रतीक्षा शर्मा ने तहरीर दी। बताया कि उनके पिता हेमराज शर्मा (57 वर्ष) एस्ले हॉल स्थित अग्रवाल फिलिंग स्टेशन पर काम करते थे। बीती छह जनवरी की शाम वह ड्यूटी खत्म कर स्कूटी से घर लौट रहे थे। इसी दौरान डालनवाला में लक्ष्मी रोड, आईबीएम टॉवर के पास कार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें एम्बुलेंस से दून अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया था। अंतिम संस्कार के बाद परिजनों ने जब घटनास्थल के आसपास पूछताछ की तो स्थानीय लोगों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता लगा कि टाटा हैरियर चालक ने हादसा किया। पुलिस ने बुधवार को कार नंबर के आधार पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन पर सख्ती, निजी वाहनों के सत्यापन के निर्देश

देहरादून। राज्य में स्कूली बच्चों के सुरक्षित आवागमन को लेकर उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना की अध्यक्षता में गुरुवार को इस विषय पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोग कार्यालय में हुई। आयोग अध्यक्ष डॉ. गीता खन्ना ने कहा कि कई ऐसे निजी वाहन, जैसे वैन, ऑटो, ई–रिक्शा व विक्रम स्कूलों द्वारा अधिकृत किए बिना बच्चों को लाने–ले जाने का कार्य कर रहे हैं, जो सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर विषय है। ऐसे सभी निजी वाहनों को आरटीओ से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने, उनका नियमित सत्यापन कराने तथा ड्राइवरों का पूरा विवरण और मानसिक स्थिति की जांच रिपोर्ट स्कूलों में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने निजी स्कूल वाहनों की पहचान के लिए येलो स्ट्रिप लगाने का सुझाव भी दिया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वाहन में स्कूली बच्चे यात्रा कर रहे हैं। साथ ही कहा गया कि प्रत्येक स्कूल के पास यह रिकॉर्ड होना चाहिए कि उसके छात्र किस परिवहन माध्यम से स्कूल आते–जाते हैं। बैठक में जनपद बागेश्वर की कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए अन्य जनपदों को उसी तर्ज पर कार्य करने के निर्देश दिए गए। आयोग ने सभी जनपदों से आ रही चुनौतियों और सुझावों को साझा करने को भी कहा। अध्यक्ष ने निर्देश दिए कि स्कूल बसों को एक्सीडेंट रिलीफ फंड से आच्छादित किया जाए तथा बड़े स्कूलों को अपने परिसर में पार्किंग की अनिवार्य व्यवस्था करनी होगी,

गुंजन हत्याकांडः देहरादून में एसआइटी ने दाखिल की चार्जशीट

देहरादून। मच्छी बाजार में हुए गुंजन हत्याकांड में एसआइटी ने चार दिन में आरोपित को चार्जशीट कर लिया है। घटना में इस्तेमाल चापड़, आरोपित के खून से सने कपड़े, जूते व हेलमेट विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए हैं। आज शुक्रवार को एसआइटी चार्जशीट की कापी कोर्ट में पेश करेगी। इसके अलावा एसआइटी न्यायालय में इस केस को फास्ट ट्रैक में केस ट्रायल के लिए पैरवी करेगी। नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) में यह पहला ऐसा मामला है जिसमें पुलिस ने चार दिन में ही आरोपित को गिरफ्तार कर चार्जशीट भी तैयार दी। दो फरवरी को शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित मच्छी बाजार में आरोपित आकाश कुमार निवासी मन्नु गंज खुड़बुड़ा ने चापड़ से अपनी दोस्त गुंजन श्रीवास्तव का गला काटकर हत्या कर दी थी। घटना के कुछ समय बाद ही पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर उसे कोर्ट के समक्ष पेश किया गया था, जहां से उसे जेल भेजा गया। प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए घटना से जुड़े साक्ष्यों का वैज्ञानिक तरीके से तत्काल संकलन कर आरोपित के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए एसएसपी अजय सिंह ने पुलिस अधीक्षक नगर प्रमोद कुमार के पर्यवेक्षण में एसआइटी का गठन किया।एसआइटी की ओर से मुकदमे में तत्काल कार्रवाई करते हुए घटनास्थल व उसके आसपास के सीसीटीवी फुटेजों का अवलोकन कर, घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्यों जुटाए गए। साथ ही आरोपित की ओर से घटना में इस्तेमाल स्कूटी को कब्जे में लेते हुए आरोपित के आने व जाने वाले रूट का चार्ट बनाया गया।

मेघालय की कोयला खदान में धमाका, 16 मजदूरों की मौत

नई दिल्ली। मेघालय के ताशखाई इलाके में स्थित एक कोयला खदान में बड़ा धमाका हुआ है। इस हादसे में कम से कम 16 मजदूरों की मौत हो गई वहीं एक घायल बताया जा रहा है। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है।

राहत व बचाव कार्य शुरू

आशंका जताई जा रही है कि मृतकों में शामिल सभी मजदूर असम के रहने वाले थे, हालांकि प्रशासन की ओर से अभी आधिकारिक पुष्टि की प्रक्रिया जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही मेघालय की पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंच गए और राहत व बचाव कार्य शुरू कर दिया है। खदान के अंदर फंसे अन्य मजदूरों की तलाश के लिए सघन सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बचाव कार्य के दौरान किसी तरह की बाधा न हो, इसके लिए प्रशासन ने आसपास के इलाके को घेरकर सुरक्षा बढ़ा दी है। अधिकारियों ने कहा कि धमाका कैसे हुआ, इसका पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

कैसे हुआ धमाका?

शुरुआती तौर पर खदान में गैस रिसाव या तकनीकी खामी को हादसे का संभावित कारण माना जा रहा है। हालांकि, जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट कारण का पता चल पाएगा।

गुड गवर्नेंस मॉडल से अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा योजनाओं का लाभ : धामी

मुख्यमंत्री धामी ने वन-क्लिक प्रणाली से 9.47 लाख से अधिक लाभार्थियों को पेंशन भुगतान किया

जयन्त प्रतिनिधि।

देहरादून : मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत पात्रता परीक्षण, सत्यापन एवं भुगतान प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ किया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक निर्बाध रूप से पहुँचता रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ह्लराज्य सरकार का संकल्प है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पहुंचे। पेंशन योजनाएं केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन का आधार हैं। हमारी सरकार गरीबों, वृद्धों, महिलाओं, दिव्यांगों और किसानों के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में

समाज कल्याण विभाग की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत माह जनवरी 2026 की पेंशन किस्त का वन-क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भुगतान किया। यह पहल राज्य सरकार की तकनीक आधारित, पारदर्शी और संवेदनशील शासन व्यवस्था को सुदृढ़ करती है तथा सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के कमजोर, वृद्ध, दिव्यांग, विधवा, किसान, निराश्रित एवं जरूरतमंद वर्गों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ समयबद्ध, पारदर्शी और तकनीक आधारित प्रणाली के माध्यम से प्राप्त हो, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कहा कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर एवं वन-क्लिक भुगतान प्रणाली से न केवल भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है, बल्कि लाभार्थियों को बिना किसी कार्यालयी प्रक्रिया के सीधे उनके बैंक खातों में सहायता राशि प्राप्त हो रही है। इससे शासन और आम नागरिक के बीच विश्वास भी सुदृढ़ हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत जनवरी 2026 माह में राज्य के 9,47,345 पात्र लाभार्थियों को पेंशन का लाभ प्रदान किया गया। इस अवसर पर अपर सचिव संदीप तिवारी सहित समाज कल्याण विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

महंगाई भत्ते पर बड़ी खबर: कर्मचारियों को मिलेगा पूरा हक

सुप्रीम कोर्ट ने किया समिति का गठन

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों को मिलने वाले मंहगाई भत्ते (डीए) पर महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि मंहगाई भत्ता कोई अतिरिक्त फायदा नहीं बल्कि यह जीने का न्यूनतम स्तर बनाए रखने का एक जरिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर

शीर्ष अदालत ने पश्चिम बंगाल के राज्य कर्मचारियों के मंहगाई भत्ता पाने के अधिकार पर मुहर लगाते हुए कहा है कि जब डीए को एक बार वैधानिक नियमों के अनुसार आल इंडिया कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स (एआइसीपीआइ) से जोड़कर परिभाषित कर दिया जाता है तो राज्य बाद में आफिस मैमोरेन्डम के जरिए इसकी गणना के तरीके को नहीं बदल सकता।

सर्वोच्च अदालत ने राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार को 2008 से 2019 की अवधि का मंहगाई भत्ता देने का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है। कोर्ट ने राज्य सरकार को अपने कर्मचारियों को छह मार्च तक डीए का 25 फीसद भुगतान करने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने गुरुवार को डीए देने के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर यह फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारी इस फैसले के अनुसार 2008–2019 की अवधि के मंहगाई भत्ते की बकाया राशि पाने के हकदार होंगे। हालांकि कोर्ट ने साथ ही कहा है कि कर्मचारी साल में दो बार डीए पाने के हकदार नहीं हैं।

कोर्ट ने फैसले में मंहगाई भत्ते के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए कहा कि मंहगाई भत्ता एक वेलफेयर स्टेट के हाथों सुरक्षा के एक व्यावहारिक साधन के रूप में सामने आता है, जो अपने कर्मचारियों को बढ़ती कीमतों के बुरे असर से बचाता है। कोर्ट ने कहा कि डीए कोई अतिरिक्त फायदा नहीं है, बल्कि ये जीने का न्यूनतम स्तर बनाए रखने का एक जरिया है। हालांकि डीए देने के आदेश के वित्तीय असर को देखते हुए कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा, हाई कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और गौतम भादुड़ी तथा कंपट्रोलर एंड आडिटर जनरल आफ इंडिया (सीएजी) या उनके द्वारा नामित वरिष्ठतम अधिकारी होंगे।

कोर्ट ने कमेटी को निर्देश दिया है कि कमेटी राज्य के अधिकारियों के साथ परामर्श करके, कर्मचारियों को भुगतान की जाने वाली कुल राशि और भुगतान का शिड्यूल तय करेगी। जिसका राज्य पालन करेगा। इसके अलावा कमेटी समय समय पर राशि जारी होने की पुष्टि करेगी।

कोर्ट का निर्देश

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि भुगतान राशि और शिड्यूल छह मार्च 2026 से पहले तय हो जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि कमेटी के फैसले के आधार पर पहली किस्त का भुगतान 31 मार्च तक किया जाएगा। कोर्ट ने फैसले में स्पष्ट किया है जो राज्य कर्मचारी इस दौरान सेवानिवृत हो गए हैं वे भी इस लाभ को पाने के अधिकारी हैं। कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार पहली किस्त का भुगतान करने के बाद कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करेगी। मामले में कोर्ट 15 अप्रैल को फिर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 16 मई 2025 को अंतरिम आदेश दिया था जिसमें राज्य सरकार को कर्मचारियों के ड्यू डीए के 25 प्रतिशत का भुगतान करने को कहा था। कोर्ट ने फैसले में मंहगाई भत्ते के व्यवहारिक पक्ष और लोगों को मंहगाई के असर से बचाने के पक्ष पर विस्तृत चर्चा की है। साथ ही इसे पाने के कानूनी और संवैधानिक अधिकार पर भी फैसले में चर्चा की गई है।

महिला का खोया बैग मिला, 2.16 लाख रुपये लौटाए

हरिद्वार। ज्वालापुर कोतवाली पुलिस की तत्परता और सीसीटीवी कैमरों की मदद से हरियाणा से बेटी की शादी के लिए हरिद्वार आई महिला का खोया बैग मिल गया। इस बैग में रखे 2.16 लाख रुपये महिला को लौटा दिए गए। इस पर महिला ने हरिद्वार पुलिस का आभार जताया। पुलिस के अनुसार, बुधवार को रोहतक हरियाणा की महिला ने कोतवाली पहुंचकर बताया कि वह बेटी की शादी के सिलसिले में रानीपुर आई थी। बस अड्डे से ई–रिक्शा में सवार होकर रानीपुर मोड़ पर उतरते समय बैग रिक्शा में ही छूट गया। महिला को न तो ई–रिक्शा का नंबर पता था और न ही चालक की पहचान।

प्रभारी निरीक्षक कुंदन सिंह राणा के निर्देश पर वरिष्ठ उपनिरीक्षक खेमेंद्र गंगवार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए पांच फरवरी को ई–रिक्शा का पता लगा लिया। ई–रिक्शा चालक के पास से बैग बरामद किया गया। चालक ने बताया कि वह महिला की तलाश कर बैग लौटाने की कोशिश कर रहा था।

नगर क्षेत्र में दो युवकों की संदिग्ध हालात में मौत

कोटद्वार। नगर क्षेत्र के अंतर्गत दो युवकों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने पंचनामे की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम कराकर युवकों के शव परिजनों के सुपुर्द कर दिए। एसआई सय्यदुल बहार ने बताया कि लालपुर निवासी दीपांशु रावत (19) पुत्र शैलेंद्र रावत को बृहस्पतिवार सुबह परिजन गंभीर हालत में बेस अस्पताल लेकर पहुंचे,जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उन्होंने परिजनों से हुई पूछताछ का हवाला देते हुए बताया कि दीपांशु ने जेईई की परीक्षा दी थी। बुधवार को आंसर–की जारी हुई थी। परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आने के कारण वह काफी व्यथित था। बृहस्पतिवार सुबह जब दीपांशु काफी देर तक कमरे से बाहर नहीं आया तो परिजन कमरे में पहुंचे। दीपांशु उन्हें गमछे के सहारे खिड़की पर लटका मिला। परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं यूपी के जिला बिजनौर की नगीना तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बिंजाहेड़ी निवासी दिनेश कुमार (19) पुत्र सर्वेश कुमार को परिजन बेस अस्पताल लाए जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि दिनेश कौड़िया में अपने बड़े भाई के साथ किराये के कमरे में रहता था और प्लंबिंग का कार्य करता था। दिनेश कमरे में अपने भाई को पंखे के हुक पर लटका मिला। दिनेश को भी अस्पताल लाया गया। उसे चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम कराया। बाद में शव परिजनों को सौंप दिए गए।

दो विभागों से लाभ ले रहे 970 लोगों की पेंशन रोकी

समाज कल्याण विभाग ने शासन को भेजी रिपोर्ट

देहरादून। समाज कल्याण विभाग ने 970 लोगों की पेंशन रोक दी है। ये वह लोग हैं, जो अपने विभागों के साथ ही समाज कल्याण विभाग से भी पेंशन ले रहे थे। विभाग मामले की पड़ताल में जुट गया है। जो जानकारी सामने आ रही है, उससे पता चलता है कि यह खेल 12 साल से चल रहा है।

विभिन्न विभागों से सेवानिवृत्त हो चुके 1377 कर्मचारी अपने विभाग के साथ ही राज्य आंदोलनकारी पेंशन समेत अन्य तरह की पेंशन भी ले रहे हैं। कैग के डाटा विश्लेषण व सत्यापन में दोहरी पेंशन लेने का मामला खुला था। इस संबंध में कैग ने शासन को पत्र भेजा था। इसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है। मामले की तह तक जाने के लिए समाज कल्याण विभाग ट्रेजरी विभाग से भी मदद ले रहा है। अधिकारियों के अनुसार 1377 ऐसे प्रकरण हैं, इनमें से 93 लोगों को मृत्यु और 314 को सत्यापन के बाद अन्य कारणों से पोर्टल से हटा दिया गया था। अभी 970 लोग ऐसे हैं, जो दोहरी पेंशन ले रहे हैं। समाज कल्याण निदेशक डॉ संदीप तिवारी ने बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। 970 लोगों की पेंशन रोकने की जानकारी दे दी गई है। आगे विस्तृत रिपोर्ट दी जाएगी। इसके बाद शासन स्तर से संबंधित लोगों से रिकवरी समेत अन्य कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा।

राज्य आंदोलनकारी की पेंशन भी ले रहे 565 लोग

समाज कल्याण विभाग के अनुसार 970 लोग दोहरी पेंशन ले रहे हैं, इनमें से 565 राज्य आंदोलनकारी या स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन ले रहे हैं। 405 अन्य लोग अन्य किस विभाग से पेंशन ले रहे हैं, उनके बारे में ट्रेजरी विभाग से जानकारी मांगी गई है।

2013–14 साल से चल रहा था खेल

दोहरी पेंशन लेने का खेल एक–दो साल से नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रहा है। जो जानकारी सामने आई है। उससे पता चलता है कि यह गड़बड़ी वर्ष 2013–2014 से चल रही है।

मणिपुर में नई सरकार के गठन के 24 घंटे के अंदर भड़की हिंसा: चुराचांदपुर में तनाव

इंफाल। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में बृहस्पतिवार को उस समय हालात तनावपूर्ण हो गए, जब लोकप्रिय सरकार गठन के विरोध में तुइबोंग इलाके में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गए। पूरे दिन जिले में माहौल तनावग्रस्त बना रहा। प्रशासन को बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ी। शाम को हालात और बिगड़ गए, जब प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए सुरक्षाबलों को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। हालांकि, विरोध प्रदर्शन सुबह से ही जारी गए थे। लेकिन प्रदर्शनकारियों का आक्रोश उस समय और भड़क उठा, जब कुकी विधायकों की तरफ से नई सरकार को समर्थन दिए जाने की जानकारी सामने आई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि विधायकों ने समुदाय की भावना की अनदेखी करते हुए यह कदम उठाया है, जबकि क्षेत्र में अलग प्रशासनिक व्यवस्था की मांग लंबे समय से उठती रही है।

क्या ट्रंप के दावे के बाद भी रूस से तेल खरीदेगा भारत?

विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब

नई दिल्ली। भारत सरकार ने वेनेजुएला और रूस से तेल खरीदने को लेकर चल रहे कयासों पर प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "सरकार ने कई मौकों पर सार्वजनिक रूप से कहा है कि 1.4 अरब भारतीयों की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है।" रणधीर जायसवाल ने कहा, "ऑब्जेक्टिव मार्केट की स्थितियों और बदलते अंतरराष्ट्रीय माहौल को ध्यान में रखते हुए अपने एनर्जी सोर्स को डाइवर्सिफाई करना इसे सुनिश्चित करने की हमारी रणनीति का मुख्य हिस्सा है। भारत के सभी फैसले इसी बात को ध्यान में रखकर लिए गए हैं और लिए जाएंगे।"

ट्रंप ने क्या कहा था?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने बीते दिनों भारत–यूएस ट्रेड डील को लेकर घोषणा की थी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेफॉर्म ट्रूथ सोशल पर पोस्ट कर लिखा था कि अब अमेरिका भारत से आने वाले सामानों पर 18 प्रतिशत का टैरिफ लगाएगा। इसके साथ ही ट्रंप ने दावा किया था कि भारत रूस से तेल खरीद रोकने पर राजी हो गया है और वह अपनी जरूरतों के लिए वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। अब इस दावे को लेकर उठे सवालों पर भारत का रिएक्शन आया है।

वेनेजुएला को लेकर क्या बोला विदेश मंत्रालय ?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वेनेजुएला को लेकर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, "जहां तक वेनेजुएला की बात है, यह एनर्जी के क्षेत्र में हमारा लंबे समय से पार्टनर रहा है, चाहे वह ट्रेड हो या इन्वेस्टमेंट।"

हम 2019–20 तक वेनेजुएला से एनर्जी और कच्चा तेल इंपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद हमें इसे रोकना पड़ा। फिर, हमने 2023–24 में वेनेजुएला से तेल खरीदना शुरू किया, लेकिन प्रतिबंध फिर से लगने के बाद हमें इसे रोकना पड़ा... एनर्जी सिक्योरिटी के प्रति अपने नजरिए के मुताबिक, भारत वेनेजुएला सहित किसी भी कच्चे तेल की सप्लाई के कमर्शियल फायदों को देखने के लिए तैयार है।

ट्रेड डील से क्या फायदा?

रणधीर जायसवाल ने कहा, "प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप से टेलीफोन पर बात की। उस कॉल के बाद और राष्ट्रपति ट्रंप के ट्वीट के बाद, प्रधानमंत्री ने आपसी टैरिफ में कमी के लिए राष्ट्रपति ट्रंप को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब मेड–इन–इंडिया प्रोडक्ट्स 18% कम टैरिफ पर अमेरिका को एक्सपोर्ट किए जाएंगे।" उन्होंने कहा, "इस ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका को हमारे एक्सपोर्ट को बड़ा बढ़ावा देगा।

धन्यवाद प्रस्ताव में योगी का जिक्र पीएम मोदी बोले

सरकार की अक्षमताओं के कारण एक बार उनके भी आंसू निकले

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने एक घंटा 27 मिनट भाषण दिया। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जिक्र करते हुए पुरानी घटना का उल्लेख किया। कहा कि सरकार की अक्षमताओं के कारण एक बार उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री जी सदन में भाषण करते–करते वो रो पड़े थे।

पीएम बोले–राहुल ने सिखों का अपमान किया

पीएम मोदी ने कहा, कल जो घटना घटी, इसी सदन के सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग युवराज ने उन्हें गद्दार कह दिया। अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच चुका है उनका। कांग्रेस को छोड़कर कितने लोग निकले हैं। कई लोग दूसरे देशों में गए हैं। और किसी को तो उन्होंने गद्दार नहीं कहा है। लेकिन कल उन्होंने सांसद को गद्दार कहा क्योंकि वो सिख थे। उनके अंदर सिखों के लिए जो नफरत भरी है, यह उसका ही उदाहरण था। जिसका परिवार देश के लिए शहादत देने वाला परिवार है, उसके वह सदस्य हैं, उन्होंने पार्टी बदल ली तो वे गद्दार हो गए। वे एक सिख हैं, इसके लिए गद्दार कहना ये दुर्भाग्य की बात है।

टीएमसी और कांग्रेस पर कही ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि हमारे तृणमूल कांग्रेस के साथियों ने बहुत कुछ कहा। निर्मम सरकार और उसके पतन के जितने भी पैरामीटर्स हैं, उन सब में वे नए रिकॉर्ड बना रहे हैं और यहां उपदेश दे रहे हैं। (बंगाल में) क्या हाल किया है। ऐसी निर्मम सरकारों से भारत का भविष्य डूब रहा है। उनके लिए महिलाओं पर अत्याचार होता है तो होते रहे, सत्ता नीति के अलावा कुछ करना नहीं है। वे हमें यहां उपदेश दे रहे हैं। ऐसे मुद्दों पर आंखें मूंदकर बैठे हुए लोग हैं।

युवक ने खुद को गोली मारकर की आत्महत्या

रुड़की। मुंडाखेड़ा खुर्द गांव में प्रधान संगठन के उपाध्यक्ष के छोटे भाई ने पारिवारिक कलह के चलते खुद को गोली मार ली। उसका शव उसके कमरे में पड़ा मिला। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस ने मौके से तमंचा भी बरामद किया है। वरिष्ठ उप निरीक्षक लोकपाल परमार ने बताया किगुरुवार तड़के जानकारी मिली कि मुंडाखेड़ा खुर्द गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। बताया कि घटना स्थल पर जाकर जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि 28 वर्षीय नकुल पिछले कुछ दिनों से पारिवारिक अवसाद से गुजर रहा था।

माध्यमिक के बाद बेसिक के 12 लाख शिक्षकों को कैशलेस चिकित्सा का आदेश जारी

लखनऊ। माध्यमिक के बाद शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग के 12 लाख शिक्षकों व उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिए जाने का शासनादेश बुधवार को जारी कर दिया। जानकारी के अनुसार इस पर आने वाले व्ययभार के लिए आगामी बजट में आवश्यक प्रावधान भी किया जाएगा। योजना के तहत बेसिक शिक्षा परिषद के मान्यता प्राप्त विद्यालयों (अनुदानित व स्ववित्तपोषित) में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्र, विशेष शिक्षक, अनुदेशक, केजीबीवी की वार्डेन, पूर्ण कालिक व अंशकालिक शिक्षकों, प्रधानमंत्री पोषण योजना के रसोइयों के आश्रितों परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए प्रति कार्मिक 3000 रुपये वार्षिक प्रीमियम अनुमानित है।

सम्पादकीय

वीआईपी कल्चर का अभिशाप

उत्तराखंड के बड़े नगरों में वीआईपी कल्चर एक मुसीबत बन चुका है। यहां कोई भी बड़ा आयोजन भारी परेशानियों बनकर सामने आ रहा है। फिर चाहे वह कोई धार्मिक आयोजन हो या फिर सरकारी। अति विशिष्ट लोगों की अगुवाई में प्रशासन आम लोगों को सड़क पर परेशानी के हाल में छोड़ देता है जो घंटे तक अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए सरकारी व्यवस्थाओं को कोसते नजर आते हैं। अभी पिछले दिनों ही उत्तराखंड के "रजत जयंती उत्सव" के दौरान कुछ कार्यक्रम एवं अति विशिष्ट लोगों के दौरे प्रदेश की राजधानी के लोगों पर बेहद भारी गुजरे। इसे विभिन्न आयोजनों के दौरान आम नागरिक बेहद परेशान नजर आते हैं। देहरादून में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान भी भारी फजियत से लोग गुजरते हैं तो हरिद्वार की जनता भी इस वीआईपी कल्चर से त्रस्त है। खास लोगों के लिए की गई व्यवस्था आम आदमी पर भारी गुजर रही है। चंद मिनट का सफर गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है, लेकिन जिला प्रशासन के पास ऐसी कोई यातायात व्यवस्था नहीं है जिससे आम लोगों को और असुविधा का सामना न करना पड़े। शायद प्रशासन किसी भी वीआईपी ड्यूटी के दौरान सिर्फ और सिर्फ वीआईपी की सुविधा को ही ध्यान में रखता है फिर चाहे पूरा शहर त्राहि त्राहि क्यों ना करता रहे? यही सब न केवल राजधानी देहरादून बल्कि विप मोमेंट के दौरान दूसरे शहरों में भी जनता को झेलना पड़ा है। शासन प्रशासन को पहले जनता की सुविधा को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि यही वह जानता है जो इन वीआईपी को उस स्तर तक पहुंचती है लेकिन ऐसे वीआईपी की अगुवाई ही उनके लिए आए दिन अब बड़ी मुसीबत बनती जा रही है। उत्तराखंड में अति विशिष्ट लोगों की सुविधा और सुरक्षा के लिए रास्ते बंद कर देना प्रशासन के लिए एक सामान्य सी बात हो गई है। इस व्यवस्था में बड़े स्तर पर सुधार करने की जरूरत है क्योंकि इस प्रकार की वीआईपी व्यवस्थाएं और एक व्यक्ति की सुविधा हजारों लाखों के लिए जी का जंजाल बन जाती है। वैसे ही राजधानी देहरादून की यात्रा व्यवस्था का हाल बद से बदतर स्थिति में है और ऐसे बड़े आयोजनों के दौरान तो शहर की स्थिति बेहद खराब हो जाती है। क्या शासन प्रशासन के पास ऐसे विकल्प नहीं है जिसमें अति विशिष्ट लोगों को आम लोगों की और असुविधा से दूर रखते हुए उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। यही स्थिति विभिन्न धार्मिक आयोजनों के दौरान निकलने वाले जुलूस एवं राजनीतिक व गैर राजनीतिक संगठनों के जुलूस प्रदर्शनों के दौरान भी जनता को झेलनी पड़ती है। इन व्यवस्थाओं में परिवर्तन की जरूरत है और जनता की सुविधा को ही शासन को सवीपरि मानना चाहिए ना कि उन्हें यातायात सुधार के नाम पर कहीं भी रोक दिया जाय या जबरन दूसरे रास्तों में भेजा जाए।

राष्ट्र निर्माण के प्रति कर्तव्य

तोखन साहू

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया केंद्रीय बजट 2026–27, सिर्फ़ एक सालाना वित्तीय बयान से कहीं ज़्यादा है; यह एक विकसित भारत बनाने का ब्लूप्रिंट है। माघ पूर्णिमा के पवित्र अवसर और गुरु रविदास जी की जयंती पर पेश किया गया यह बजट एक गहरे नैतिक और राष्ट्रीय उद्देश्य को दर्शाता है। ऐतिहासिक 53.5 लाख करोड़ के कुल खर्च और लगभग 27 लाख करोड़ के पूंजीगत खर्च के साथ, यह बजट राजकोषीय समझदारी बनाए रखते हुए भारत की विकास गाथा में विश्वास का संकेत देता है, जिसमें घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.3त्न पर सीमित है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह युवा भारतीयों की आकांक्षाओं को दर्शाता है, जिनके विचार प्रधानमंत्री के विकसित भारत युवा नेता संवाद के दौरान साझा किए गए थे और उन्हें राष्ट्रीय नीति निर्माण में जगह मिली है। यह विकास सिर्फ़ दफ़्तरों में नहीं, बल्कि नागरिकों के साथ बातचीत के ज़रिए आकार दिया गया है।

3 कर्तव्यों से प्रेरित और हमारे युवाओं की आकांक्षाओं से निर्देशित, यह बजट विकास और समावेश, महत्वाकांक्षा और करुणा के बीच संतुलन बनाता है। पहला कर्तव्य आर्थिक विकास को तेज़ करने और बनाए रखने पर केंद्रित है, जो एक विकसित अर्थव्यवस्था की नींव रखेगा। 10,000 करोड़ का बायोफार्मा मिशन, सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, और महत्वपूर्ण खनिजों, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग, कंटेनर उत्पादन और मेगा टेक्सटाइल पार्क को मजबूत करने के उपाय घरेलू उद्योग को बढ़ावा देंगे और आयात पर निर्भरता कम करेंगे। ये दूरदर्शी क्षेत्र भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में मजबूती से स्थापित करते हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का इंजन को एक बड़ा बढ़ावा मिला है, जिसमें फ्रेट कॉरिडोर, जलमार्ग और मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय में 12.2 लाख करोड़ का प्रावधान है। शहरी आर्थिक क्षेत्र, हाई–स्पीड रेल कॉरिडोर और म्युनिसिपल बॉन्ड प्रोत्साहन शहरों को उत्पादकता के केंद्र बनाएंगे, लॉजिस्टिक्स लागत कम करेंगे, निवेश आकर्षित करेंगे और बड़े पैमाने पर रोज़गार पैदा करेंगे।

दूसरा कर्तव्य लोगों के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देता है। हेल्थकेयर संस्थानों में निवेश, संबद्ध स्वास्थ्य कार्यबल का विस्तार, और बुजुर्गों की देखभाल सेवाएं सामाजिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करती हैं। यूनिवर्सिटी टाउनशिप और हर जिले में महिलाओं के हॉस्टल जैसी शिक्षा पहल पहुंच और सुरक्षा में सुधार करती हैं, जबकि पर्यटन, विरासत विकास और खेलो इंडिया मिशन युवाओं के लिए नए अवसर खोलते हैं।

तीसरा कर्तव्य, सबका साथ, सबका विकास के मार्गदर्शन में, समावेशी विकास सुनिश्चित करता है। किसानों को मत्स्य पालन, पशुधन और उच्च मूल्य

वाली कृषि के साथ–साथ जल निकायों के विकास के माध्यम से सहायता मिलती है। मानसिक स्वास्थ्य देखभाल में निवेश और पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए केंद्रित पहल संतुलित क्षेत्रीय प्रगति को बढ़ावा देती हैं। यह दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि भारत की विकास यात्रा में कोई भी समुदाय या क्षेत्र पीछे न छूटे।

छत्तीसगढ़ के लिए यह बजट अवसरों का एक नया अध्याय खोलता है। भारत को ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए प्रस्तावित ?10,000 करोड़ के निवेश से राज्य को फायदा होगा, जिससे राज्य में निवेश, रिसर्च और हाई–क्वालिटी नौकरियों के अवसर आएंगे। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 में शामिल होने से छत्तीसगढ़ एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरने में मदद मिलेगी। प्रोसेसिंग यूनिट्स स्थापित करके, राज्य ओडिशा के साथ मिलकर रेयर मेटल कॉरिडोर से रणनीतिक और औद्योगिक रूप से भी लाभ उठा सकता है।

टेक्सटाइल सेक्टर में पहल – जिसमें नेशनल फाइबर मिशन, टेक्सटाइल विस्तार और रोज़गार योजना, और मेगा टेक्सटाइल पार्क शामिल हैं – छत्तीसगढ़ के पारंपरिक शिल्प, हथकरघा, खादी और आधुनिक टेक्सटाइल उद्योगों को नई गति देंगे। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करेगी और स्थानीय कारीगरों की आय बढ़ाएगी। एमएसएमई के लिए बजटीय सहायता यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य में छोटे और मध्यम उद्यमों को अधिकतम लाभ मिले, जिससे स्वरोज़गार और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।

कार्बन कैप्चर, यूटिलाइज़ेशन और स्टोरेज के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान छत्तीसगढ़ को अपने समृद्ध वन संसाधनों को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के ज़रिए आर्थिक लाभ में बदलने का अवसर देता है। शिक्षा के क्षेत्र में, राज्य में कम से कम एक यूनिवर्सिटी टाउनशिप की स्थापना और हर ज़िले में एक महिला छात्रावास उच्च शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक समावेश को मज़बूत करेगा। हर ज़िले में ट्रॉमा सेंटर की स्थापना, बुजुर्गों की देखभाल सेवाओं का विस्तार, और राज्य में एक अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने के प्रयासों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मज़बूत किया जाएगा।

टियर–2 और टियर–3 शहरों में कॉर्पोरेट फैसिलिटेटर की शुरुआत से स्थानीय युवाओं के लिए रोज़गार के नए अवसर पैदा होंगे और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा। मछली पालन, अमृत सरोवरों के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट, पशुपालन, डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग, और हाई–वैल्यू एग्रीकल्चर के लिए सपोर्ट से किसानों की आय बढ़ेगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मज़बूत होगी। खेलो इंडिया मिशन के ज़रिए, छत्तीसगढ़ के एथलीटों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने के अवसर मिलेंगे।

शहरी विकास के लिए, अर्बन इकोनॉमिक रीजन्स के लिए 5,000 करोड़ का आवंटन और म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने के लिए प्रोत्साहन छत्तीसगढ़ के शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक क्षमता को मज़बूत करेगा। नए इनकम टैक्स एक्ट, आसान टैक्स नियमों, टीडीएस/टीसीएस के युक्तिकरण, और कस्टम ड्यूटी में राहत जैसे सुधार टैक्स सिस्टम को नागरिकों, उद्योगों और निवेशकों के लिए ज़्यादा पारदर्शी, सरल और निष्पक्ष बनाएंगे।

इस बदलाव की यात्रा के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व है। राष्ट्र निर्माण, युवा सशक्तिकरण और समावेशी विकास पर उनका अटूट ध्यान भारत के विकास पथ को लगातार आकार दे रहा है। उनके मार्गदर्शन में, सुधार धीरे–धीरे नहीं बल्कि संरचनात्मक हैं, अल्पकालिक नहीं बल्कि पीढ़ियों तक चलने वाले हैं। केंद्रीय बजट 2026–27 इसी दर्शन को दर्शाता हैः एक आत्मविश्वासी भारत जो अपने लोगों, अपने राज्यों और अपने भविष्य में निवेश कर रहा है, और 2047 तक विकसित भारत के साझा राष्ट्रीय लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ रहा है।

एआई में आत्मनिर्भर भारत की तैयारी

सुशील पाल

कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई आज की सबसे ताकतवर और तेजी से बदलने वाली तकनीक में से एक बनती जा रही है। इसमें यह क्षमता है कि यह देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे, उत्पादन बढ़ाए और विकास की रफ्तार तेज करे। सरकारी सेवाओं को ज्यादा प्रभावी और पारदर्शी बनाने में भी एआई अहम भूमिका निभा सकती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बीमारी की शुरुआती पहचान, खेती में सही समय पर सही फैसले लेने, आपदा से पहले चेतावनी देने, मौसम और जलवायु का बेहतर अनुमान लगाने और सरकारी योजनाओं का लाभ आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने में एआई पहले से ही मदद कर रही है। आने वाले समय में शिक्षा, परिवहन और उद्योग जैसे क्षेत्रों में भी एआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने की संभावना है।

लेकिन जैसे पहले की तकनीकी क्रांतियों में हुआ, वैसे ही एआई के साथ भी असमानता की तस्वीर सामने आती है। जिनके पास कंप्यूटर की ताकत यानी कंप्यूट, अच्छा डेटा और मजबूत डिजिटल ढांचा है, वही बड़े स्तर पर एआई का लाभ उठा पा रहे हैं। जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं, वे पीछे रह जाते हैं। यह फर्क आज केवल कंपनियों के बीच ही नहीं, बल्कि देशों और इलाकों के बीच भी साफ दिखाई देता है।

भारत ने इस चुनौती को एक अवसर के रूप में लिया है। इंडिया एआई मिशन के जरिए भारत यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि एआई की ताकत कुछ गिने–चुने लोगों तक सीमित न रहे। कंप्यूट, डेटा और एआई मॉडल को डिजिटल सार्वजनिक सुविधा के रूप में देखा जा रहा है, ताकि स्टार्टअप, शोधकर्ता, छात्र और छोटे संस्थान भी एआई पर काम कर सकें। भारत की सोच साफ है– ऐसा डिजिटल ढांचा बनाया जाए जो खुला हो, आसानी से बढ़ सके और समाज के हर वर्ग के काम आए। इससे एआई का लाभ आम लोगों तक पहुंचे, देश में ही नवाचार को बढ़ावा मिले और तकनीक के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन सके।

इस सोच के पीछे एक ठोस योजना है। दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि भारत एआई को पांच स्तरों पर विकसित कर रहा है– बिजली और ऊर्जा, कंप्यूट और इंफ्रास्ट्रक्चर, चिप और हार्डवेयर, एआई मॉडल और एप्लिकेशन। इन सभी पर एक साथ काम होने से ही एआई का सही और व्यापक उपयोग संभव हो पाएगा। भारत का तरीका इसलिए अलग है क्योंकि यहां एआई तक पहुंच आसान बनाई गई है। भारत ने एक साझा कंप्यूट प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहां 38,000 जीपीयू एक ही पोर्टल पर मिलते हैं। इनका खर्च करीब 65 रुपये प्रति घंटा है, जबकि दूसरे देशों में इसके लिए 2.5 से 3 डॉलर प्रति घंटा तक देने पड़ते हैं। इंडिया एआई मिशन के तहत सरकार एआई मॉडल बनाने के लिए पूरी लागत (100 प्रतिशत) तक मदद दे रही है और एआई के इस्तेमाल पर भी 40 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है। इससे पैसे की कमी एआई पर काम करने में रुकावट नहीं बनती। इसी वजह से सरवम एआई, सोकेट एआई और ज्ञानि एआई जैसे भारतीय स्टार्टअप अब बिना बड़ी पूंजी लगाए अपने खुद के एआई और भाषा मॉडल बना पा रहे हैं, जो पहले सिर्फ बड़ी विदेशी कंपनियां ही कर पाती थीं।

भारत का लक्ष्य सिर्फ एआई का इस्तेमाल करना नहीं, बल्कि अपना एआई बनाना है। भारत अपना खुद का एआई मॉडल तैयार कर रहा है, जो भारतीय भाषाओं, भारतीय संस्कृति और भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। इसे इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट (16–20 फरवरी 2026) में पेश किए जाने की उम्मीद है। यह मॉडल भारत के ही डेटा पर प्रशिक्षित होगा और देश के भीतर ही काम करेगा।

इससे एआई ज्यादा सटीक, निष्पक्ष और सबको साथ लेकर चलने वाला बनेगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित होगा कि डेटा सुरक्षित रहे और एआई का इस्तेमाल देश के कानूनों और नागरिकों के अधिकारों के अनुसार हो।

इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में एआई को लेकर केवल जोखिमों की चर्चा नहीं होगी, बल्कि यह देखा जाएगा कि एआई जमीन पर क्या बदलाव ला रही है। इसमें एआई को सबके लिए उपलब्ध कराने, विकास में इसके उपयोग, पर्यावरण की रक्षा, भरोसेमंद सिस्टम, भारतीय भाषाओं में एआई, ग्लोबल साउथ की भागीदारी और एआई से जुड़ी असमानताओं को कम करने जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा। भारत का यह तरीका उन देशों के लिए भी एक उदाहरण है, जो अभी विकास के रास्ते पर हैं। यह दिखाता है कि खुलेपन और नवाचार के साथ–साथ अपनी तकनीकी स्वतंत्रता कैसे बनाए रखी जा सकती है। भारत अपने एआई मॉडल ओपन–सोर्स के रूप में विकसित कर रहा है, ताकि दूसरे देश भी अपनी जरूरतों के अनुसार इन्हें अपना सकें। मकसद है मिलकर आगे बढ़ना, बिना किसी नई निर्भरता के।

न्याय की व्यापक समझ को तिलांजलि

समस्या आनुपातिक समानता के नाम पर दशकों से चल रही वो राजनीति है, जिसमें न्याय की व्यापक समझ को तिलांजलि दे दी गई है। इस सोच ने समाज को पुरानी जकड़नों में और भी मजबूती से बांध डाला है।

उच्च शिक्षण संस्थानों में कथित जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा–निर्देशों ने नई सामाजिक हलचल पैदा कर दी है। इससे संबंधित अपने आरंभिक ड्राफ्ट में आयोग ने दो बदलाव किए। उससे ये मामला भड़का है। शुरुआती ड्राफ्ट में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के साथ जातीय आधार पर भेदभाव के मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया शामिल थी। उसमें यह प्रावधान भी था कि गलत शिकायत दर्ज कराने वाले छात्र (या कर्मचारी) पर क्या कार्रवाई होगी। ड्राफ्ट का समाज के एक हिस्से की तरफ से विरोध हुआ। उसके दबाव में आकर यूजीसी ने एक तो संभावित उत्पीड़न का शिकार होने वाले समूहों में ओबीसी जातियों को शामिल कर दिया और दूसरे गलत शिकायत से संबंधित प्रावधान को हटा दिया।

नतीजा सामान्य श्रेणी वर्ग में गहरे असंतोष के रूप में सामने आया है। इन समूहों की दलील है कि जाति आधारित भेदभाव का शिकार वो भी होते हैं। इस समझ के मुताबिक जातिगत भेदभाव ताकत एवं प्रभाव की स्थिति में मौजूद हर अधिकारी कर सकता है, भले वह किसी जाति से आया हो। उनके मुताबिक यूजीसी इक्विटी विनियमन 2026 की भाषा ऐसी है, जिससे संदेश जाता है कि हर मामले में उत्पीड़क सामान्य श्रेणी के लोग ही होते हैं। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक यूजीसी इस तर्क से सहमत नहीं है और जल्द ही वह इस बारे में स्पष्टीकरण जारी करेगा।

अगर ये खबर सच है, तो अपेक्षित होगा कि यूजीसी फौरन ऐसा करे। वरना, ये विवाद एक नई सामाजिक अशांति का कारण बनता नजर आ रहा है। वैसे, इस तरह के मामलों में तमाम तरह के स्पष्टीकरणों की अपनी सीमा है। समस्या आनुपातिक समानता के नाम पर दशकों से चल रही वो राजनीति है, जिसमें न्याय की व्यापक समझ को तिलांजलि दे दी गई है। इस सोच ने समाज को पुरानी जकड़नों में और भी मजबूती से बांध डाला है। चूंकि इस सोच में जाति के अलावा पिछड़ेपन, शोषण, एवं भेदभाव के कहीं अधिक मूलभूत दूसरे कारणों को सिरे से नजरअंदाज किया गया है, इसलिए जकड़नों को तोड़ कर आगे बढ़ने की दृष्टि और सामाजिक प्रगति के रास्ते बाधित हो गए हैं।

ओ रोमियो का नया गाना इश्क का फीवर जारी

विशाल भारद्वाज की फिल्म ओ रोमियो रिलीज के लिए तैयार है। शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी अभिनीत इस फिल्म के अब तक दो गाने रिलीज हो चुके हैं, जिन्हें काफी पसंद भी किया गया। अब फिल्म निर्माताओं ने फिल्म का तीसरा गाना इश्क का फीवर रिलीज किया है, जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है। जी हां! अरिजीत सिंह, जिन्होंने हाल ही में प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास की घोषणा की थी, अब एक नया गाना लेकर आए हैं। हालांकि, प्रशंसकों को अरिजीत की आवाज सुनकर खुशी तो हुई, लेकिन साथ ही वे इस बात को लेकर भी चिंतित नजर आ रहे हैं कि कहीं यह उनका आखिरी गाना तो नहीं है।

ओ रोमियो के संगीतकार और निर्देशक विशाल भारद्वाज ने अरिजीत की प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट की पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया था। वीडियो में विशाल और अरिजीत के साथ रेखा भारद्वाज भी नजर आ रही हैं, जबकि निर्देशक और संगीतकार इश्क का फीवर गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब यह गाना रिलीज हो चुका है! ऐसे में अरिजीत सिंह के फैंस भी इमोशनल हो गए और सिंगर से अपना फैसला वापस लेने की अपील कर रहे हैं। कई ने वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए सिंगर से वापसी की गुहार लगाते दिखे।

अरिजीत सिंह और विशाल भारद्वाज ने हिंदी सिनेमा के कुछ सबसे यादगार गाने एक साथ बनाए हैं, जैसे कि फिल्म हैदर का खुल कभी तो और रंगून का ये इश्क है।

गोलमाल 5 में करीना कपूर की वापसी पक्की, रोहित शेट्टी की सबसे बड़ी पलटन तैयार

रोहित शेट्टी की ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फ्रेंचाइजी गोलमाल 5 को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। फिल्म में करीना कपूर की वापसी पक्की हो गई है, जो एक बार फिर अजय देवगन के साथ स्क्रीन शेयर करेंगी। इस बार रोहित शेट्टी ने अक्षय कुमार को भी इस फिल्म से जोड़कर एक बड़ा कास्टिंग धमाका किया है। अजय, अक्षय और करीना जैसे सितारों के साथ गोलमाल 5 की ये पलटन अब तक की सबसे बड़ी टीम मानी जा रही है।

फिल्म से जुड़े सूत्र ने बताया, करीना की कास्टिंग में थोड़ा समय लगा, क्योंकि तारीख और कुछ अन्य मुद्दों पर बातचीत चल रही थी। रोहित शेट्टी और अजय देवगन उन्हें फिल्म में लेने के लिए बेहद उत्सुक थे, वहीं करीना भी गोलमाल फ्रेंचाइजी में लौटने को लेकर उत्साहित थी। रोहित की टीम ने करीना के लिए एक बेहद मजेदार और अनोखा रोल तैयार किया है, जिसके लिए आखिरकार बात बन गई है। ट्रेड पंडितों का मानना है कि गोलमाल 5 को लेकर पहले ही काफी उत्साह था, क्योंकि इसके सभी पिछले चारों भाग सफल रहे हैं। अब अक्षय की एंट्री और करीना की वापसी ने फिल्म के प्रति रोमांच को दोगुना कर दिया है।

डेड बॉल से बाउंड्री कैचिंग समेत क्रिकेट के कई नियम में हुए बदलाव

नईदिल्ली,क्रिकेट की दुनिया में मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब (एमसीसी) नियम व कानून बनाने में अहम भूमिका निभाता है. जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) इन नियमों को मैच में लागू करता है. ये नियम इस बात पर असर डालते हैं कि खेल कैसे खेला जाता है और समझा जाता है.

एमसीसी ने 2026 एडिशन जारी किया है, जिसमें खेल के नियमों में किए गए बदलाव पर जोर दिया गया है. इसे दो साफ उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया है. क्रिकेट के कानून बनाने वाले इस क्लब ने कुल 73 नियमों में संशोधन किए हैं, लेकिन इनमें से 8 नियमों में बदलाव सबसे अहम हैं.

सबसे ज्यादा असरदार बदलावों में से एक टेस्ट क्रिकेट में हुआ है, जहां, अब तक, दिन के आखिरी ओवर में विकेट गिरने पर खेल तुरंत खत्म हो जाता था, जिससे आने वाले बल्लेबाज बाकी गेंदों

का सामना करने से बच जाते थे. लेकिन अब अक्टूबर 2026 से, आउट होने के बावजूद आखिरी ओवर पूरा खेला जाएगा. ये बदलाव उस नतीजे को खत्म करते हैं जिसे फील्डिंग टीम के लिए गलत माना जाता था.जानबूझकर शॉर्ट रन के लिए पहले से ही पांच रन की पेनल्टी है, लेकिन अपडेटेड नियम में एक कड़ी सजा जोड़ी गई है. जिसमें अब, फील्डिंग टीम ये चुनेगी कि अगली गेंद पर कौन सा बल्लेबाज स्ट्राइक पर रहेगा. इस तरह, फील्डिंग कप्तान अब इस नियम का इस्तेमाल एक टैक्टिकल हथियार के तौर पर कर सकते हैं, और कमजोर बल्लेबाज को स्ट्राइक पर ला सकते हैं. एक फील्डर जो बाउंड्री लाइन के बाहर से कूदकर कैच करता है, वह हवा में रहते हुए गेंद को सिर्फ एक बार छू सकता है. उस टच के बाद, उसे बाकी गेंद के लिए खेल के मैदान के अंदर पूरी तरह से जमीन पर होना चाहिए.पहले, डेड बॉल उस गेंद को माना जाता था कि गेंद गेंदबाज या विकेट–कीपर के हाथों में होनी चाहिए. अब, बॉल को डेड माना जाएगा अगर उसे कोई फील्डर पकड़ ले या वह जमीन पर स्थिर हो जाए. विकेट–कीपर को अब बॉलर के रन–अप के दौरान स्टंप्स के सामने ग्लव्स रखने पर पेनल्टी नहीं लगेगी. यह पेनल्टी अब तभी लागू होगी जब गेंदबाज के हाथ से गेंद रिलीज हो जाएगी.अगर कोई बैटर शॉट खेलने के बाद बैलेंस खोकर स्टंप्स पर गिर जाता है, तो उसे आउट माना जाएगा क्योंकि उसे बॉल खेलने की क्रिया में माना जाएगा. अगर कोई बैटर फील्डर से टकरा कर स्टंप्स पर गिरता है या फिर उसका कोई पार्ट उससे अलग होकर स्टंप्स पर लग जाता है, तो उसे नॉट आउट दिया जाएगा.

पेचिदा मर्डर मिस्ट्री सुलझाते नजर आएंगे मोना सिंह–बरुण सोबती

नेटफ्लिक्स की क्रिटिक्स द्वारा सराहे गए इन्वेस्टिगेटिव क्राइम ड्रामा, 'कोहराझ़ का दूसरा सीजन अब कमबैक कर रहा है. पुलिस के किरदारों में बरुण सोबती और मोना सिंह एक सनसनीखेज मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करते नजर आएंगे. फिलहाल मेकर्स ने कोहरा 2 का ट्रेलर रिलीज किया है जो जबरदस्त है. ट्रेलर देखने के बाद फैंस सीरीज की रिलीज का इंतजार नही कर पा रहे हैं.पहले सीज़न की सक्सेस के बाद, कोहरा सीजन 2 को लेकर एक्साइटमेंट भी कई गुना बढ़ गई है. वहीं मेकर्स ने इसका धांसू ट्रेलर जारी कर दिया है. 2 मिनट 13 सेकंड का यह क्लिप सब–इंस्पेक्टर धनवंत कौर (मोना सिंह स्टारर) को यह बताए जाने के साथ शुरू होता है कि वह एक नए केस की जांच कर रही हैं. वह अपने साथी,

पुलिस के असिस्टेंट सब–इंस्पेक्टर अमरपाल जसजीत गरूंडी (बरुण सोबती द्वारा अभिनीत) को प्रीत बाजवा के मर्डर वाली जगह पर ले जाती हैं, बिना रुके, पुलिस केस की जांच शुरू करती है, पहले प्रीत के भाई से पूछताछ करती है जैसे–जैसे दोनों अधिकारी मामले की गहराई में जाते हैं, जांच न केवल शहर के रहस्यों को उजागर करना शुरू कर देती है, बल्कि उनकी अपनी पर्सनल कमजोरियों का भी खुलासा करती जाती है.

जैसे–जैसे आधिकारिक प्रक्रियाएं आगे बढ़ती हैं, संदिग्धों की सूची लगातार बढ़ती जाती है, जिसमें पीड़ित का पति भी शामिल है, जिसे रणविजय सिंघा ने निभाया है, जबकि उसका भाई, जिसका किरदार अनुराग अरोड़ा ने निभाया है, खुद को मामले में और गहराई से फंसा हुआ पाता है.

सरफराज खान अस्पताल में भर्ती

मुंबई,मुंबई क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज सरफराज खान को वायरल बुखार के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में शुक्रवार से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स पर कर्नाटक क्रिकेट टीम के खिलाफ शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी क्वार्टरफाइनल में उनका खेलना संदिग्ध है। बुधवार को सरफराज मुंबई टीम के साथ मौजूद थे, जब दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर ने खिलाड़ियों के साथ खास संवाद सत्र आयोजित किया था। रिपोर्ट के अनुसार, सरफराज को वायरल बुखार है, जिसके चलते उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी तबीयत ठीक नही है, इसी वजह से वह दिल्ली के खिलाफ मुंबई के पिछले मैच में फील्डिंग के लिए भी मैदान पर नही उतर सके थे।

टी–20 विश्व कप के इतिहास में भारतीय टीम द्वारा बनाए गए सबसे बड़े स्कोर

नईदिल्ली,टी–20 विश्व कप के इतिहास में भारतीय क्रिकेट टीम ने कई बार अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से दुनिया को हैरान किया है। बड़े मंच पर खेले गए मुकाबलों में भारतीय टीम ने ऐसे विशाल स्कोर खड़े किए, जिन्होंने विरोधी टीमों की कमर तोड़ दी। ये स्कोर सिर्फ रन नहीं, बल्कि भारतीय बल्लेबाजों की आक्रामक सोच और ताकत का प्रतीक हैं। ऐसे में आइए भारतीय टीम द्वारा बनाए गए टी–20 विश्व कप में सबसे बड़े स्कोर पर नजर डाल लेते हैं।

भारतीय क्रिकेट टीम ने साल 2007 के विश्व कप में इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाफ 218/4 का स्कोर बना दिया

था। पहले बल्लेबाजी करते हुए गौतम गंभीर ने 41 गेंदों में 58 रन बनाए थे। वीरेंद्र सहवाग के बल्ले से 52 गेंदों में 68 रन निकले थे। युवराज सिंह ने तो सिर्फ 16 गेंदों में 58 रन जड़ दिए थे। जवाब में इंग्लैंड की टीम 200/6 का स्कोर बना पाई थी। भारत को 18 रन से शानदार जीत मिली थी। भारतीय टीम का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर साल 2021 के टी–20 विश्व कप में आया था। टीम ने अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाफ 210/2 का स्कोर बनाया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने 47 गेंदों का सामना करते हुए 74 रन बनाए थे। ऋषभ पंत ने 13 गेंद में 27 रन और हार्दिक पांड्या ने 35 रन बनाए थे। केएल राहुल के बल्ले से 69 रन निकले थे। जवाब में अफगानिस्तान 144/7 का स्कोर ही बना पाई थी।

एक नजर

श्रीनगर में होगा पीएम राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन

श्रीनगर गढ़वाल : राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) श्रीनगर में 9 फरवरी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन होगा। मेला सुबह साढ़े 10 बजे से शुरू होगा। मेले में पौड़ी जिले समेत गढ़वाल मंडल के विभिन्न जनपदों के युवा प्रतिभाग करेंगे। प्रधानाचार्य राजीव कुमार ने बताया कि मेले में पांचवीं, आठवीं, दसवीं, बारहवीं, आईटीआई, डिप्लोमा एवं स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को विभिन्न नामी कंपनियों के प्रतिनिधियों के समक्ष साक्षात्कार का अवसर मिलेगा। चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि के लिए अप्रेंटिस के रूप में नियोजित किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप अवधि के दौरान युवाओं को ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी साथ ही शासन की ओर से निर्धारित मानदेय भी दिया जाएगा। (एजेंसी)

जनप्रतिनिधियों ने दी क्रमिक अनशन की चेतावनी

श्रीनगर गढ़वाल : ब्लॉक की ग्राम पंचायत पाब अकरी में न्याय पंचायत सेमी सेमला के जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। बैठक में क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं का समाधान न किए जाने पर जनप्रतिनिधियों ने 10 फरवरी से पाब अकरी में क्रमिक अनशन शुरू करने की चेतावनी दी। इसके बाद भी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आमरण अनशन किया जाएगा।पूर्व जिला पंचायत सदस्य महिपाल सिंह बुटोला की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनप्रतिनिधियों और अन्य लोगों ने न्यूली पेयजल योजना का पुनर्गठन न करने, अकरी बारजूला पंपिंग पेयजल योजना से पर्याप्त पेयजल आपूर्ति न होने, सेल से मठूरगांव मार्ग का निर्माण न किए जाने समेत कई समस्याओं पर आक्रोश जताया। कहा कि शासन-प्रशासन ने क्षेत्र की इन समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया है। इस कारण क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। बैठक में अकरी बारजूला संघर्ष समिति के संरक्षक कुंजकृष्ण डंगवाल, अध्यक्ष लक्ष्मण सिंह, सचिव प्रेम सिंह नेगी, संयोजक राकेश कोहली, संजय देव डंगवाल, प्रधान अंकिता, जगदीश लाल, कुलदीप मियां व क्षेत्र पंचायत सदस्य सुशील चंद्र आदि मौजूद थे। (एजेंसी)

प्रयत्नशील रहने का दिया संदेश

श्रीनगर गढ़वाल : गढ़वाल विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग तथा साहित्यिक क्लब की ओर से लेखिका एवं सामाजिक कार्यकर्ता महाश्वेता देवी की जन्म-शताब्दी पर साहित्यिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गढ़वाल विवि के कुलपति प्रो. श्रीप्रकाश सिंह ने कविता के माध्यम से लोगों को जीवन जीने की कला बताई और विकट परिस्थितियों में प्रयत्नशील रहने का संदेश दिया। अंग्रेजी विभाग की विभागाध्यक्ष प्रो. मोनिका गुप्ता ने साहित्यिक गतिविधियों में बढ़-चढ़कर भागीदारी करने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर डीन प्रो. मंजुला रणा, मुख्य नियंता प्रो. दीपक व अन्य फैकल्टी सदस्य मौजूद रहे। (एजेंसी)

वनों को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया

श्रीनगर गढ़वाल : वन चेतना केंद्र कीर्तिनगर वन विभाग की ओर से जैव विविधता संरक्षण पर गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में वन एवं वन्य जीवों को वनों की आग से बचाने एवं जैव विविधता संरक्षण व सामूहिक सहभागिता की आवश्यकता के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही आने वाले फायर सीजन में वनों को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया गया, जिससे पर्यावरण संतुलन बनाए रखा जा सके। इस मौके पर उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड, देहरादून से डॉ. अमित सिंह, चमोली से सचिन चौहान, कीर्तिनगर रेंज के वन क्षेत्राधिकारी संजय सिंह बेलवाल, उप वन क्षेत्राधिकारी सुखदेव बडोनी, वन दरोगा सुभाष, वन आरक्षी राजेश बिष्ट और किशन रावत आदि मौजूद रहे।

श्रीनगर पहुंची मां चंडिका की दिवारा यात्रा

श्रीनगर गढ़वाल : जिलासू से निकली मां चंडिका की दिवारा यात्रा बृहस्पतिवार को श्रीनगर पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने मां के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मां की यात्रा काला रोड, गोला बाजार, गणेश बाजार और सब्जी मंडी से होते हुए हाईवे तक पहुंची। रास्ते में श्रद्धालुओं ने यात्रा का स्वागत किया। रात्रि विश्राम के लिए यात्रा कमलेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। शुक्रवार को यात्रा गंगा स्नान के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार जाएगी। इसके बाद यात्रा उत्तरकाशी स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए रवाना होगी।

निगम वसूल रहा तहबाजारी, जनता हो रही परेशान

शहर में लगातार बढ़ती जा रही रेहड़ी-ठेली की संख्या

गोखल मार्ग में सड़क किनारे लगी फल-सब्जी की रेहड़ी-ठेलियां

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : नगर में रेहड़ी–फड़ों पर फल-सब्जी बेचने वाले व्यापारियों से वसूली जाने वाली नगर निगम की तहबाजारी आमजन की मुसीबतें बढ़ा रहा है। नगर निगम में भले ही डेढ़ सौ रेहड़ी-ठेली पंजीकृत हों। लेकिन, नगर निगम प्रतिदिन क्षेत्र में एक हजार से अधिक रेहड़ी-फड़ वालों से तीस रूपए प्रतिदिन के हिसाब से तहबाजारी वसूल रहा है। इससे भले ही निगम के राजस्व में बढ़ोत्तरी हो रही हो। लेकिन, आमजन के लिए सड़कों पर लगने वाली फल-सब्जी की रेहड़ी-फड़ परेशानी का सबब बनी हुई है।

शहर में शायद ही कोई ऐसी सड़क हो, जहां आपको फल-सब्जी की रेहड़ी-फड़ न दिखाई दे। पूरे दिन सड़कों पर घूम रहे यह रेहड़ी-ठेली वाले यातायात के साथ ही अन्य व्यवस्थाओं में बाधा बन रहे हैं। सबसे बुरी स्थिति बदरीनाथ मार्ग, गोखले मार्ग, पटेल मार्ग, स्टेशन रोड व देवी रोड पर बनी हुई है। सड़क पर सफेद पट्टी के बाहर खड़ी इन रेहड़ी-ठेलियों के कारण आमजन का पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। नियमानुसार, शहर में घूमने वाली सभी रेहड़ी-ठेलियों का नगर निगम में पंजीकृत होना आवश्यक है। जिसके बाद नगर निगम उन्हें एक स्थाई जगह उपलब्ध करवाता है। लेकिन, कोटद्वार शहर में नगर निगम रेहड़ी-ठेली वालों को केवल आर्थिकी का जरिया बना रहा है। जबकि, आज तक धरातल पर उनके लिए कई स्थाई जगह चिह्नित नहीं की गई। निगम की इसी लापरवाही के कारण शहर में लगातार रेहड़ी-ठेली वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में यदि इस ओर सख्ती से ध्यान नहीं दिया गया तो चुनौतियां और अधिक बढ़ सकती है।

कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा

उत्तर प्रदेश के विभिन्न गांव से प्रतिदिन सैकड़ों रेहड़ी-ठेली वाले शहर में पहुंचते हैं। शहर में सब्जी व फल बेच रहे इन लोगों के बारे में नगर निगम व पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं होती। ऐसे में यदि यह कोई आपराधिक घटना को अंजाम देते हैं तो पुलिस के हाथ खाली ही रहेंगे। जबकि, पूर्व में कई बार गोखले मार्ग में महिलाओं के साथ टप्पेबाजी की घटनाएं भी हो चुकी हैं। जिसके बाद शहरवासियों ने पुलिस व निगम से रेहड़ी-ठेली व फड वालों का सत्यापन करने की मांग उठाई। लेकिन, सरकारी सिस्टम ने इस ओर गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। कई रेहड़ी-ठेली वाले नगर निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्ड की गलियों में भी घूमते रहते हैं।

दुगड्डा में आयोजित कार्यशाला में भाग लेते लोग

ग्रामीणों को सिखाएं बेहतर खेती के गुर

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकास्ट) की ओर से ग्रामीणों को खेती के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कहा कि आर्थिकी को मजबूत बनाने के लिए ग्रामीणों को स्वरोजगार को अपनाना चाहिए।

राजकीय इंटर कालेज दुगड्डा में माटी जैव विविधता संरक्षण व सामाजिक शोध संगठन देहरादून की ओर से यूकास्ट के सहयोग से कार्यशाला आयोजित किया गया। कार्यशाला में ग्रामीणों को मशरूम उत्पादन के साथ ही औषधीय पौधों को उगाने के बारे में जानकारी दी गई। कहा कि बहुत कम लागत में ग्रामीण बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। खंड विकास अधिकारी बीडी रतूड़ी ने कहा कि ग्रामीणों को अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। ग्रामीणों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए भी सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। इस मौके पर मुख्य प्रशिक्षक संगीता, डा. अंकिता राजपूत, डा. वेदप्रकाश, सुनील कुमार, डा. अंकिता राजपूत, डा. जोखन शर्मा आदि मौजूद रहे।

गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग को यूकेडी ने निकाली रैली

चमोली : उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) ने बृहस्पतिवार को देवाल बाजार में रैली निकाली और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने रैली के माध्यम से लोगों से यूकेडी को मजबूत करने की अपील की। रैली में खेता, बलाण, मानमती, घेस, सुयालकोट घाटी व पिंडर के कई गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। लोगों ने जय पहाड़, जय पहाड़ी... के नारे भी लगाए। इसके बाद ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन करते हुए हेम चंद्र मिश्रा को अध्यक्ष चुना गया। यूकेडी के केंद्रीय महामंत्री चंद्र मोहन गड़िया ने कहा कि प्रदेश के लोगों का अब भाजपा और कांग्रेस पार्टी से मोह भंग हो गया है। ऐसे में अब लोग यूकेडी पर अपना भरोसा जता रहे हैं। हर दिन लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। निश्चित ही 2027 के चुनावों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ब्लॉक सभागार में आयोजित बैठक में ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन करते हुए हेम चंद्र मिश्रा को ब्लॉक अध्यक्ष चुना गया। इस मौके पर वीर सिंह पंवार, पूजा मिश्रा, हीरा सिंह फर्स्वाण, देवेंद्र उनियाल, भरत सिंह राणा, सुरेंद्र टम्टा, भगवान सिंह बिष्ट, पंकज मिश्रा, भवान सिंह आदि शामिल रहे। (एजेंसी)

वीरेंद्र कुमार बनें प्रभागीय अध्यक्ष

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : उत्तराखंड वन विकास निगम कर्मचारी के द्विवर्षिय चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई। इस दौरान सर्वसम्मति से वीरेंद्र कुमार को प्रभागीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। पदाधिकारियों ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कार्यों के निर्वहन का संकल्प लिया। चुनाव अधिकारी चंद्रपाल सिंह व सहायक चुनाव अधिकारी अश्वनी कुमार के दिशा-निर्देश पर कार्यकारिणी का गठन किया गया। कार्यकारिणी मे वीरेंद्र कुमार को प्रभागीय अध्यक्ष, विनोद कुमार को उपाध्यक्ष, पुष्पेंद्र कुमार को मंत्री, सैयद जुबेर को संगठन मंत्री, अल्का रावत को कोषाध्यक्ष, जयदीप पुंडीर को संयुक्त मंत्री, हरपाल सिंह को प्रचार मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। दिनेश रावत को कार्यकारणी सदस्य की जिम्मेदारी दी गई। इस मौके पर क्षेत्रीय अध्यक्ष दलवीर सिंह रावत, पूरन राठौर, जीवन सिंह, मुकेश बड़थ्वाल, मधुबाला रौथाण आदि मौजूद रहे।

भाजपा के राज में बिगड़ रही कानून व्यवस्था

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को भेजा ज्ञापन

कोटद्वार तहसील में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन देते कांग्रेसी

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : उत्तराखंड में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था पर कांग्रेस ने रोष व्यक्त किया है। कहा कि भाजपा के कार्यकाल में लगातार कानून व्यवस्था बेपटरी होती जा रही है। महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। सड़क पर खुलेआम हत्या की घटनाएं सामने आ रही है। कहा कि प्रदेश में व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है।

इस संबंध में कांग्रेस ने प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। वक्ताओं ने कहा कि सत्ता में आने से पूर्व भाजपा ने बेहतर कानून व्यवस्था का वादा किया। लेकिन, वर्तमान में प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है। बेखौफ बदमाश सरेआम निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। लचर कानून व्यवस्था के चलते देहरादून व ऋषिकेश में तीन महिलाओं की हत्या हो गई है। कोटद्वार में दीपक कुमार पर हुड़दंगियों ने खुलेआम गाली-गलौच कर हमले का प्रयास किया। कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार हेट स्पीच दे रहे है, जिससे पूरे प्रदेश का माहौल बिगड़ रहा है। कहा कि महिला अपराधों में हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड पहले नंबर पर पहुंच गया है। उन्होंने बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला अत्याचार व सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाली घटना व हेट स्पीच पर रोक लगवाने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देशित करने की मांग की है। इस मौके पर महिला कांग्रेस की पूर्व प्रदेश महामंत्री रंजना रावत, रमेश चंद्र खंतवाल, बलवीर सिंह रावत, प्रेम सिंह पयाल, लक्ष्मी चौहान, बीरेंद्र सिंह रावत, चंद्रमोहन सिंह रावत, प्रदीप नेगी, नरेंद्र सिंह नेगी, परमानंद पातीराम ध्यानी, आशाराम मौजूद रहे।

पूर्व सैनिकों ने किया यूजीसी अधिनियम का विरोध

आयोजित बैठक में भाग लेते पूर्व सैनिक

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : पूर्व सैनिक संघर्ष समिति ने यूजीसी अधिनियम का विरोध करते हुए केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग उठाई। कहा कि इससे शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होगी। देश के भविष्य को देखते हुए अधिनियम को जल्द वापस लिया जाना चाहिए।

समिति के अध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें समिति की बैठक में पूर्व सैनिकों ने यूजीसी बिल को देश के भविष्य के लिए खतरा बताया। कहा कि इस तरह के निर्णय से शिक्षा का स्तर कमजोर होगा। युवाओं में जातिवाद को लेकर तरह–तरह के विचार उत्पन्न होंगे। कहा कि पूरे देश में यूजीसी बिल का विरोध हो रहा है। बावजूद सरकार इस तरह के निर्णय ले रही है। जनता के हित में बेहतर योजनाएं बनाई जानी चाहिए, न कि विवाद पैदा करने वाली स्थिति तैयार करनी चाहिए। बैठक में निर्णय लिया गया कि समिति का स्थापना दिवस 16 फरवरी को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। साथ ही बैठक में समिति की सदस्यता शुल्क में बढ़ोत्तरी का भी निर्णय लिया गया। पूर्व सैनिकों ने सरकार से वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों को भी दूर करने की मांग उठाई। इस मौके पर समिति के अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह रावत, शूरवीर खेतवाल, राजेश बिष्ट, देवेंद्र सिंह बिष्ट, ठाकुर सिंह, नंदन सिंह, गोपाल सिंह नेगी आदि मौजूद रहे।

निराशाजनक रहा मुख्यमंत्री का कोटद्वार दौरा

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : किसान नेता पातीराम ध्यानी ने 31 जनवरी को मुख्यमंत्री के कोटद्वार दौरे को निराशाजनक बताया है। कहा कि मुख्यमंत्री ने कोटद्वार को किसी भी तरह की सौगात नही दी। जबकि, जनता को विकास की बेहतर योजनाओं के घोषणा की उम्मीद थी।पातीराम ध्यानी ने कहा कि स्थानीय जनता पिछले कई वर्षों से बेहतर विकास की उम्मीद कर रही है। लेकिन, विकास के नाम पर केवल जनता को गुमराह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कुछ छोटी योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण करने की घोषणा कर वापस चले गए। जबकि कोटद्वार को जिला बनाए जाने, मेडिकल कालेज, लालढांग-चिलरखाल मोटर मार्ग को रामनगर तक जोड़ने को लेकर एक शब्द भी नही कहा। कहा कि कोटद्वार में मेडिकल कालेज के लिए भूमि भी चयनित है, जहां पर खननकारियों ने गहरे गड्ढे कर दिए है। चारदीवारी को भी नुकसान पहुंचा दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने लालढांग-चिलरखाल मोटर मार्ग के सुधारीकरण के लिए आधी-अधूरी घोषणा की है, जबकि यह मार्ग गढ़वाल व कुमाऊं मंडल को जोड़ता है, जिसको जनहित में बनाया जाना जरूरी है। कहा कि कोटद्वार जिला भी भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में है। लेकिन, कोटद्वार को जिला बनाने के लिए भी कोई घोषणा नही हुई है। उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्य करवाने के लिए प्रदेश सरकार को निर्देशित करने की मांग की है।

मेरुड़ा न्याय पंचायत में लगा बहुउद्देश्यीय शिविर, 44 शिकायतें दर्ज

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान के तहत विकासखंड जयहरीखाल की न्याय पंचायत मेरुड़ा में बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 537 लोगों ने प्रतिभाग किया। इस दौरान 44 शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। वहीं 251 लोगों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया गया।

गुरुवार को आयोजित शिविर में अपर सचिव पंचायतीराज श्याम सिंह ने प्रतिभाग कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने कई मामलों का मौके पर समाधान करते हुए शेष शिकायतों के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। अपर सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार का यह अभियान ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं और सेवाओं को सीधे लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कहा कि ऐसे शिविरों से आमजन को योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। उन्होंने अधिकारियों से अधिक से अधिक पात्र लोगों को योजनाओं से जोड़ने पर जोर दिया। शिविर में 23 विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां मौके पर ही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख रणवीर सजवाण, ज्येष्ठ उप प्रमुख सुरेन्द्र नेगी, एसडीओ कालागढ़ टाइगर रिजर्व लैंसडाउन शिप्रा वर्मा, अधिशासी अभियंता लोनिवि विवेक कुमार, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी लैंसडाउन बीरेंद्र भट्ट, जिला पंचायतीराज अधिकारी जितेंद्र कुमार, खंड विकास अधिकारी रवि सैनी, ग्राम प्रधान मेरुड़ा सुनीता देवी सहित अन्य विभागों के अधिकारियों और स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

सीमा पर भारी पुलिस फोर्स, नहीं पहुंचे चंद्रशेखर

कौड़िया चैक पोस्ट के में तैनात पुलिस कर्मी

जयन्त प्रतिनिधि।

कोटद्वार : सोशल मीडिया पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के कोटद्वार पहुंचकर दीपक से मिलने की पोस्ट वायरल हो रही थी। जिसे देखते हुए पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली थी। गुरुवार को कोटद्वार के कौड़िया चैक पोस्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया। लेकिन, देर शाम तक भी चंद्रशेखर कोटद्वार नहीं पहुंचे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की विशेष टीमें सीमाओं पर तैनात है।

मालूम हो कि, 26 जनवरी को कोटद्वार में एक दुकान का नाम बदलने को लेकिन विवाद हो गया था। 31 जनवरी को बड़ी संख्या में कोटद्वार पहुंचे बजरंगदल व विश्व हिंदू परिषद के युवक कोटद्वार पहुंचे और मामले से सबंधित युवक दीपक के जिम के बाहर प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने किसी तरह मामले को संभाला। लेकिन, अब भी सोशल मीडिया पर कई लोग मामले को लेकर टिप्पणी कर रहे हैं। एक दिन पूर्व ही सोशल मीडिया पर भीम आर्मी चीफ व सांसद चंद्रशेखर आजाद के कोटद्वार पहुंचे की पोस्ट वायरल हुई। इसके बाद शहर में हरिद्वार, पौड़ी सहित अन्य स्थानों की पुलिस को बुलाया गया। गुरुवार को भारी पुलिस फोर्स को उत्तराखंड-उत्तर प्रदेश की सीमा पर तैनात कर दिया गया। पुलिस ने उत्तर प्रदेश की ओर से आने वाले वाहनों की तलाशी ली। साथ ही पार्टी का झंडा लगाकर चलने वाले वाहनों में बैठे लोगों से सख्ती से पूछताछ की। वहीं, लालढांग-चिल्लरखाल में भी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक प्रदीप नेगी ने बताया कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस गंभीरता से कार्य कर रही है।

पूर्ण हो चुके कार्यों को पोर्टल पर अपडेट करें अधिकारी : डीएम

जयन्त प्रतिनिधि। चमोली : जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला सभागार गोपेश्वर में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिन कार्यों के लिए टेंडर प्रक्रिया होनी अवशेष हैं, उनके टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कर समय से सभी कार्यों का पूर्ण करने के साथ ही जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें पोर्टल पर अपडेट करें साथ ही उन्होंने निर्देशित कि पोर्टल पर फोटोग्राफ अपलोड करने से पहले अधिकारी स्वयं अपने स्तर पर निरीक्षण कर उन्हें अपलोड करवायें।

जिलाधिकारी ने संसद सदस्यों के द्वारा ऑफलाइन स्वीकृत कार्यों की जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2020-21 से 2023-24 तक कुल 237 लाख की धनराशि प्राप्त हुयी है जिसमें से 234 लाख की योजनाएं पूर्ण कराई जा चुकी है एवं अवशेष कार्यों को जल्द ही पूर्ण करा लिए जाएगें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी, परियोजना निदेशक आनन्द सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अभिषेक गुप्ता एवं सभी खण्ड विकास अधिकारी वीसी के माध्यम से जुड़े रहे।

कार्यालय खण्ड विकास अधिकारी एकेश्वर गढ़वाल

पत्रांक 1300/2–लेखा/आपदा/विज्ञप्ति/2025-26 दिनांक 5-2-2026

विज्ञप्ति

जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्र संख्या आर 12/103/13-मु0ग0ले0 (दै0आ0)/2025-26 दि0 06/12/2025 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों की मरम्मत / पुर्ननिर्माण हेतु धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त इस कार्यालय में पंजीकृत ठेकेदारों से (ठेकेदार द्वारा वर्ष 2024-25 में टैक्स जमा कर दिया हो) निम्नलिखित क्षतिग्रस्त मरम्मत कार्यों हेतु निविदायें दि0 13-02-2026 के दोपहर 1 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदायें दि0 13-02-2026 को ठेकेदार या उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख दोपहर 2 बजे से खोल दी जाऐगी। निविदा फॉर्म के साथ रु0 100/– का स्टाम्प पेपर, स्वीकृत धनराशि का 2 प्रतिशत की राशि सी0डी0आर0 के रूप में जो कि खण्ड विकास अधिकारी एकेश्वर के नाम बन्धक हो तथा टैक्स जमा का प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना आवश्यक है। अन्यथा की स्थिति में निविदा फॉर्म निरस्त समझा जाऐगा। क्षतिग्रस्त मरम्मत कार्य 30 दिन के अन्दर पूर्ण करना आवश्यक है। निविदा स्वीकृत / अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है।

क्र0	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि ला0 में	निविदाफार्म का मूल्य जीएसटी सहित पूर्ण रू0 में
1-	ग्राम बछेली में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक रास्ते का निर्माण कार्य।	1.10	590.00
2-	ग्राम इसोटी में पंदेरा जाने वाले क्षतिग्रस्त सार्वजनिक रास्ता/पुस्ता निर्माण कार्य।	1.50	590.00
3-	ग्राम इसोटी में आनन्द सिंह के घर के पास क्षतिग्रस्त सार्वजनिक रास्ता/पुस्ता निर्माण कार्य।	1.40	590.00
4-	ग्राम गोर्ली में किशोरीलाल के घर के पास क्षतिग्रस्त सार्वजनिक रास्ता/ पुस्ता निर्माण कार्य।	1.30	590.00
5-	ग्राम गोर्ली में सड़क से श्रीकोटखाल से विशेष्वरी के घर के पास क्षतिग्रस्त सार्वजनिक रास्ता/पुस्ता निर्माण कार्य।	1.40	590.00
6-	ग्राम गोर्ली में सुनील सिंह के घर के पास क्षतिग्रस्त सार्वजनिक रास्ता/पुस्ता निर्माण कार्य।	1.40	590.00
7-	ग्राम जैंतोली मल्ली में रविन्दर के घर के पास क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सी0सी0 निर्माण कार्य।	1.50	590.00
8-	ग्राम बीरोमल्ला में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक रास्ते का निर्माण कार्य।	1.10	590.00
9-	ग्राम बीरोमल्ला में सतीश के घर के पास क्षतिग्रस्त सार्वजनिक रास्ता/ पुस्ता निर्माण कार्य।	1.60	590.00
10-	ग्राम किमोली तल्ली में सड़क से मुन्नी देवी के घर तक क्षतिग्रस्त सार्वजनिक रास्ता / पुस्ता निर्माण कार्य।	1.50	590.00
11-	ग्राम गोर्ली में जागीधार में सड़क से गांव जाने वाला क्षतिग्रस्त सार्वजनिक रास्ता/पुस्ता निर्माण कार्य।	1.60	590.00
12-	ग्राम चमडल में सड़क से गांव तक क्षतिग्रस्त रास्ता/ पुस्ता निर्माण कार्य।	1.60	590.00
13-	ग्राम किमोली मल्ली में सार्वजनिक रास्ता/ पुस्ता निर्माण कार्य।	1.55	590.00
14-	ग्राम गोर्ली में गम्भीर सिंह के घर के पास क्षतिग्रस्त सार्वजनिक रास्ता/ पुस्ता निर्माण कार्य।	1.65	590.00
15-	ग्राम जैंतोली मल्ली में बचन सिंह के घर के पास क्षतिग्रस्त रास्ता / पुस्ता निर्माण कार्य।	1.85	590.00
16-	ग्राम सालकोट में पेयजल योजना क्षतिग्रस्त सार्वजनिक पुस्ता निर्माण कार्य।	1.35	590.00
17-	ग्राम धरासू में प्रेम सिंह के घर के पास क्षतिग्रस्त सार्वजनिक रास्ता/पुस्ता निर्माण कार्य।	1.60	590.00

खण्ड विकास अधिकारी
एकेश्वर गढ़वाल

जनपद स्तर से ग्राम स्तर तक समितियों को सक्रिय रखें : डीएम

वनाग्नि रोकथाम को लेकर जिलाधिकारी ने ली बैठक

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने जिला कार्यालय स्थित एनआईसी कक्ष में वनाग्नि रोकथाम को लेकर बैठक लेते हुए सभी विभागों को समन्वित, सक्रिय और जमीनी स्तर पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि समय से पूर्व की गई तैयारी ही वनाग्नि से होने वाली क्षति को न्यूनतम कर सकती है तथा इसमें जनसहभागिता की अहम भूमिका है।जिलाधिकारी ने कहा कि वनाग्नि के सभी संभावित कारणों को ध्यान में रखते हुए जनपद स्तर से ग्राम स्तर तक बनी समितियों को सक्रिय रखा जाए। आग की घटनाओं की रोकथाम हेतु उपलब्ध उपकरणों की समुचित जांच, मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता तथा फायर वाचरों की तैनाती की जाए। उन्होंने निर्देश दिये कि आग लगाते हुए पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जाए। साथ ही सभी वन प्रभागों में वनाग्नि की सूचनाओं के आदान-प्रदान हेतु कंट्रोल रूम की स्थापना कर उनका व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाए तथा आपात स्थिति में त्वरित सूचना तंत्र को प्रभावी बनाया जाए। उन्होंने जिला मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रीय कार्यालयों संस्थानों के अधिकारियों को निर्देश दिये सभी अधिकारी अपने-अपने कार्यालय के आसपास घास-फूस, कूड़ा करकट व झाड़ियों की नियमित सफाई बनाये रखें। वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशीन और अतिसंवेदनशील स्थलों के आसपास की बसावटों यथा गांवों, कसबों की मैपिंग प्राथमिकता के अधार पर करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने युवा कल्याण अधिकारी को निर्देश दिये कि ग्राम स्तर पर बने सभी युवा एवं महिला मंगल दलों व ग्राम प्रहरियों को सक्रिय रखें। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. शिवमोहन शुक्ला, अधीक्षण अभियंता जल संस्थान प्रवीण सैनी, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, जिला युवा कल्याण एवं प्रान्तीय रक्षक दल अधिकारी रविन्द्र फोनिया सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

जिले में 260 क्रू स्टेशन स्थापित

बैठक में बताया गया कि जनपद का 61.38 प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है। वनाग्नि का सर्वाधिक खतरा 15 फरवरी से 15 जून के मध्य रहता है। जनपद में 5795.50 हेक्टेयर क्षेत्र अति संवेदनशील तथा 70717 हेक्टेयर क्षेत्र संवेदनशील श्रेणी में है। वर्तमान में 260 क्रू स्टेशन स्थापित किये गए हैं। प्रभागीय वनाधिकारी पौड़ी वन प्रभाग महातिम यादव ने बताया कि वनाग्नि रोकथाम के दृष्टिगत जनपद में कुल 09 कंट्रोल रूम स्थापित किये गये हैं। पर्याप्त संख्या में क्रू स्टेशनों की स्थापना की जा चुकी है तथा फायर वाचरों की तैनाती की प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने बताया कि ग्राउण्ड लेवल पर मॉक ड्रिल, शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसके अलावा वन अग्नि रोकथाम के क्रम में लीसा विदोहन की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है।

पांच वर्षों से अधूरा है धनोल्टी में मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का निर्माण कार्य

डीएम ने शीघ्र पार्किंग का कार्य शुरू न करने पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के दिए निर्देश

नई टिहरी। पर्यटन नगरी धनोल्टी में मल्टी स्टोरी कार पार्किंग का निर्माण कार्य पांच वर्षों से अधर में लटका हुआ है। स्थानीय लोगों की शिकायत पर डीएम ने लोनिवि थत्यूड़ के अधिकारियों को शीघ्र पार्किंग का कार्य शुरू न करने पर ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए हैं। टिहरी जिले की धनोल्टी पर्यटन नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। धनोल्टी में वाहन पार्किंग की सुविधा न होने के कारण पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों को वाहनों को पार्क करने में भारी परेशानी उठानी पड़ती है। वर्ष 2018 में धनोल्टी में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूलर अर्बन कलस्टर योजना के तहत करीब 4: 50 करोड़ से बनने वाली दो मंजिला कार पार्किंग की स्वीकृति मिली थी। लोक निर्माण विभाग थत्यूड़ ने कार पार्किंग के टेंडर जारी कर ठेकेदार पार्किंग तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी । पांच वर्ष बीत जाने के बाद कार पार्किंग का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। निर्माण कार्य लगा ने ठेकेदार पार्किंग का निर्माण कार्य अधूरा छोड़ दिया, जिससे पार्किंग का कार्य अधर में लटक गया। पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य तपेंद्र बेलवाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष धनोल्टी रघुवीर चंद रमोला, होटल एसोसिएशन अध्यक्ष यशपाल बेलवाल आदि ने बताया कि पर्यटन नगरी धनोल्टी में पूरे वर्ष भर पर्यटकों की आवाजाही लगी रहती है। यात्रा और गर्मियों के सीजन, बर्फबारी में भारी संख्या में पर्यटक धनोल्टी घूमने के लिए आते हैं, लेकिन पार्किंग की सुविधा के अभाव में वह अपने वाहनों को जहां जगह मिलती है, वहीं पर खड़ा कर देते हैं, जिससे बाजार में जाम की स्थिति भी बन जाती है। बताया व्यापार मंडल और स्थानीय लोगों के संघर्ष के बाद धनोल्टी में 60 छोटे वाहनों की दो मंजिला पार्किंग की स्वीकृत हुई थी।उम्मीद थी, कि जल्द पार्किंग का निर्माण पूरा हो जाएगा।

सीवरेज सिस्टम से जुड़ेंगे नई टिहरी शहर के छूटे पांच हिस्से

नई नई टिहरी। नगर के छूटे पांच हिस्सों को सीवरेज सिस्टम से जोड़ने की कवायद जल्द शुरू होने की उम्मीद है। करीब 74 करोड़ की लागत से शहर का सीवरेज सिस्टम ठीक किया जाएगा। जिला मुख्यालय के एम ब्लॉक, ढुंगीधार, केमसारी, मुस्लिम मोहल्ला, के ब्लॉक अब तक सीवरेज सिस्टम से वंचित हैं। यहां पर रहने वाले लोग लंबे समय इन हिस्सों को सीवरेज सिस्टम से जोड़ने की मांग करते आ रहे हैं। धन के अभाव के कारण यह स्थान सीवरेज सिस्टम से जुड़ने से वंचित रह गए थे। सरकार ने नई टिहरी, भागीरथी पुरम, कोटी कॉलोनी और टिहरी झील के विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) सहायता प्राप्त टिहरी झील विकास परियोजना से नई टिहरी शहर के छूटे हिस्सों को सीवरेज सिस्टम जोड़ने के लिए पर्यटन विभाग को करीब 74 करोड़ की धनराशि उपलब्ध करवाई है जिससे शहर के छूटे सभी पांचों हिस्सों को जोड़ने के लिए करीब 10 किलोमीटर लंबी सीवरेज लाइन बिछेगी। साथ ही भागीरथी पुरम में पांच एमएलडी का नया सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का नवनिर्माण किया जाएगा।वर्ष 2005 में टीएचडीसी ने शहर का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद प्रशासन और नगर पालिका को शहर हैंडओवर कर दिया था। पांचों क्षेत्रों सीवरेज सिस्टम से जुड़ने के बाद के स्थानीय लोगों की परेशानी दूर होने के साथ जल संस्थान और नगर पालिका को भी राहत मिलेगी। नई टिहरी शहर में सीवरेज सिस्टम से वंचित पांच पॉकेटों को सीवरेज सिस्टम से जोड़ने के लिए एडीबी से पर्यटन विभाग को धन प्राप्त हो गया है।

गैरसैंण अस्पताल में सुधरने लगी व्यवस्थाएं

चमोली : गैरसैंण अस्पताल की सेहत में सुधार होने लगा है। विभाग ने यहां चार विशेषज्ञ चिकित्सक तैनात कर दिए हैं। इनमें महिला रोग विशेषज्ञ ने बीते सप्ताह की कार्यभार लिया है। ऐसे में अब लोगों को अस्पताल में उपचार मिलने की उम्मीद बंध गई है। ग्रीष्मकालीन राजधानी के अस्पताल गैरसैंण में सुविधाओं के लिए लोग आंदोलित थे। बीते वर्ष लोगों ने कई बार यहां प्रदर्शन किया। इसके बाद यहां बाल रोग विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञ की तैनाती हुई। बीते माह ही अस्पताल में महिला रोग और निश्चेतक की तैनाती कर दी गई है। विशेषज्ञ चिकित्सकों के अभाव में ग्रामीणों को उपचार के लिए 50 किमी. दूर कर्णप्रयाग और 70 किमी. से अधिक दूर रानीखेत जाना पड़ता था। सीएमओ डॉ. अभिषेक गुप्ता ने बताया कि गैरसैंण में हाल ही में शासन ने महिला रोग विशेषज्ञ की तैनाती की थी। इस पर बीते सप्ताह महिला रोग विशेषज्ञ डॉ. शिल्पा ने अस्पताल में तैनाती दे दी है। इससे पहले यहां निश्चेतक ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिया था। जबकि बाल रोग और हड्डी रोग विशेषज्ञ पहले ही तैनात थे। अस्पताल में चार-पांच मेडिकल ऑफिसर भी तैनात हैं। (एजेंसी)

विभाग योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाएं : डीएम

जिलाधिकारी ने की स्वरोजगार परक योजनाओं की समीक्षा

जयन्त प्रतिनिधि।

पौड़ी : विभिन्न स्वरोजगार परक योजनाओं के तहत गठित जिला प्राधिकृत समिति, जिला स्तरीय समीक्षा समिति तथा जिला स्वरोजगार प्रोत्साहन एवं अनुश्रवण समिति की संयुक्त बैठक जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया की अध्यक्षता में कलक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी विभागों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे से संबंधित नक्शा प्रकरणों को पर्यटन अधिकारी एवं एएमए जिला पंचायत को आपसी समन्वय से निस्तारित करने को कहा गया, ताकि स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सके।

जिलाधिकारी ने जिला स्तरीय समीक्षा समिति के अंतर्गत सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिये कि लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति की अद्यतन सूचना प्रस्तुत की जाए तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का फॉलोअप करते हुए एक पखवाड़े के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

डेयरी विभाग को गंगा गाय महिला डेयरी विकास योजना के अंतर्गत बैंक स्तर पर लंबित आवेदनों को एक सप्ताह में निस्तारित कराने तथा दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना के लक्ष्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिये गये। जिला स्वरोजगार प्रोत्साहन एवं अनुश्रवण समिति के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत लक्षित 725 इकाइयों का लक्ष्य पूर्ण करने, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास होम स्टे विकास योजना के 20 लक्ष्यों को समय पर पूरा करने तथा उद्यान विभाग की प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के 40 लक्ष्यों को प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। पशुपालन विभाग को बकरी पालन एवं गौपालन योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को तय समयसीमा में पूरा करने को कहा गया है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, प्रबंधक उद्योग राजेन्द्र आर्या, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी एन.के. ओझा, मुख्य पशुचिकित्साधिकारी डॉ. विशाल शर्मा, जिला पर्यटन एवं विकास अधिकारी खुशाल सिंह नेगी सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

मल्टी स्पेशियलिटी हेल्थ कैंप में 200 बच्चों की हुई जांच

एनएचएम द्वारा पीजी कॉलेज अगस्त्यमुनि में हुआ आरबीएसके विशेषज्ञ हेल्थ कैंप

जयन्त प्रतिनिधि।

रूद्रप्रयाग : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तत्वाधान में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत अगस्त्यमुनि में ब्लाक स्तरीय मल्टी स्पेशियलिटी हेल्थ कैंप का आयोजन हुआ, जिसमें जन्म से 18 वर्ष तक के 200 बच्चों की स्वास्थ्य जांच की गई।

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय अगस्त्यमुनि में आयोजित मल्टी स्पेशियलिटी कैंप में मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा दूरस्थ गांवों से आए 200 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर दवा वितरित की गई। साथ ही 14 की अल्ट्रासाउंड व 26 के खून से संबंधित विभिन्न जांच भी की गई। शिविर में अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. वैभव नौटियाल द्वारा 09, सर्जन डॉ. विवेक कुमार द्वारा 15, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. सिद्धार्थ शर्मा द्वारा 51, ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. शिखा भट्ट द्वारा 31, मनोरोग विशेषज्ञ डॉ. रिद्धा द्वारा 03, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. अजय गोस्वामी द्वारा 38 के अलावा स्त्री रोग के 53 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. राम प्रकाश ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संदर्भित बच्चों को विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से ब्लाक स्तरीय मल्टी स्पेशियलिटी कैंप का आयोजन किया गया। इससे पूर्व गत दिसंबर माह में ऊखीमठ में भी ब्लाक स्तरीय मल्टी स्पेशियलिटी कैंप का आयोजन किया गया।

इस मौके पर प्राचार्य डॉ. जितेंद्र कुमार, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त्यमुनि डॉ. अक्षिता ममगाईं, जिला कार्यक्रम प्रबंधक हिमांशु नौडियाल, डॉ. नीरजा बिष्ट, डॉ. कमल, डॉ. विजय, डॉ. नितिन, डॉ. साक्षी, डॉ. दीपिका खंडूड़ी, आरबीएसके मैनेजर सुमन, बीपीएम मुदित मैठाणी, ब्लाक लेखा प्रबंधक बलवंत बजवाल, आरकेएसके काउंसलर विपिन सेमवाल, जयदीप कुमार, मूल्यांकन व निगरानी अधिकारी नागेश्वर बगवाड़ी, शोसल वर्कर दिगपाल कंडारी, फार्मेसिस्ट युद्धवीर गुसाईं, विवेक खन्ना, दिपेंद्र सजवाण, एएनएम रेखा कांडपाल आदि मौजूद रहे।

सीडीओ ने ली रिप की समीक्षा बैठक

रुद्रप्रयाग : मुख्य विकास अधिकारी राजेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना (रिप) की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला परियोजना प्रबंधक सरिता जोशी, जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर कार्यरत स्टाफ की ओर से अपने-अपने क्षेत्रों की वित्तीय वर्ष 2025-26 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की जानकारी दी।

इस दौरान सीडीओ राजेंद्र सिंह रावत ने वेसाइड एमिनिटीज, कलेक्शन सेंटर तथा एग्री सर्विस सेंटर की प्रगति पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन सुविधाओं के माध्यम से ग्रामीण उद्यमिता को सशक्त किया जा सकता है तथा स्थानीय उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराया जा सकता है। (एजेंसी)

भाजपा ने टिप्पणी करने पर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की

देहरादून। भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल ने संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर अभद्र व अमर्यादित टिप्पणी करने के विरोध में शहीद भगत सिंह चौक पर नारेबाजी की।

उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया। गुरुवार को भाजपा मसूरी मंडल ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला जोरदार नारेबाजी के बीच दहन किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि राहुल गांधी ने संसद में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बारे में आपत्ति जनक टिप्पणी की जिससे पूरे विश्व में सिख समुदाय चिंतित है।

आरोप लगाया कि कांग्रेस की नीति यही रही है कि अल्पसंख्यकों को दबाया जाए व प्रताड़ित किया जाए। कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं है। कहा कि राहुल गांधी अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उन्होंने कांग्रेस के इस कथन की सिख समुदाय सहित भाजपा कड़ी निंदा की व कांग्रेस के नेताओं को ऐसी बयान बाजी से दूर रहने की सलाह दी। नगर पालिकाध्यक्ष मीरा सकलानी ने भी राहुल गांधी के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की व कहा कि ऐसे बयान देकर कांग्रेस नें अल्पसंख्यकों के विरोध की पराकाष्ठा पार की है। इससे पूरे देश का अल्पसंख्यक समाज आहत है। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल,पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, उपाध्यक्ष अरविंद सेमवाल, जगजीत कुकरेजा, देवेंद्र मलासी, विजय बुटोला, ज्ञान अग्रवाल, जगदीश भटट, सोबन मेहरा, सचिन पंवार, ज्योति पुंडोरा, उज्जवल नेगी आदि मौजूद रहे।

पटरी व्यवसायी महिला के निधन पर श्रद्धांजलि दी

देहरादून। रेहड़ी पटरी कमजोर वर्ग जनकल्याण समिति ने शहीद स्थल झूलाघर पर पीड़ित पटरी व्यवसायी महिला रीता माहेश्वरी के निधन पर शोक सभा का आयोजन किया। उनकी मौत का जिम्मेदार नगर पालिका को ठहराया। कांग्रेस नेत्री सोनिया आंनद रावत ने रीता माहेश्वरी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि रेहड़ी पटरी वालों की इस तरह मृत्यु हो जाना दुःखदायी है। रीता कड़ाके की ठंड के बावजूद वह पटरी लगा रही थी जिससे उसकी तबियत खराब हुई। इससे पहले भी एक पटरी वाली महिला की मृत्यु हो चुकी है।संगीता की धरना देते समय तबियत खराब हो गयी थी, उसके बावजूद भी नगर पालिका उनका उत्पीड़न कर रही है। सरकार को इनके लिए उचित व्यवस्था बनानी होगी।कहा कि इस तरह की तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलेगी। मालरोड की रौनक पटरी वालों के हटने से समाप्त हो गयी। अगर पालिका ने सुध नहीं ली तो यह चिंता का विषय है अगर आवाज नहीं उठायी गयी तो उग्र आंदोलन किया जायेगा। इसके लिए नगर पालिका दोषी है, उनको रास्ता निकालना चाहिए।शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि पटरी वालों को आंदोलन स्वरोजगार के लिए था। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, उनके बारे में पालिका को सोचना होगा।

स्कूल पहुंचे प्रमुख सचिव, बच्चों से पूछे गणित के सवाल

देहरादून। सरकारी स्कूलों में शिक्षा व मूलभूत सुविधाओं की स्थिति जानने के लिए प्रमुख सचिव डॉ. आर मीनाक्षी सुंदरम ने गुरुवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय केशरवाला का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कक्षा में बच्चों से संवाद कर उनकी शैक्षणिक समझ का आकलन किया और विद्यालय की समग्र व्यवस्थाओं का जायजा लिया। प्रमुख सचिव ने बच्चों से गणित के प्रश्न पूछे और उनकी पढ़ाई की प्रगति के बारे में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि निरीक्षण का उद्देश्य यह देखना था कि विद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय सही ढंग से पढ़ाए जा रहे हैं या नहीं। निरीक्षण में विद्यालय के शौचालय स्वच्छ पाए गए तथा बच्चों को पौष्टिक मध्याह्न भोजन दिया जा रहा था।उन्होंने यह भी बताया कि कुछ समय पूर्व बाधित हुआ दूध वितरण अब पुनः शुरू कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी देहरादून अभिनव शाह भी उपस्थित रहे।

जिला प्रशासन ने शुरू की गैरसैंण में विधानसभा बजट सत्र आयोजन की तैयारियां

जिलाधिकारी ने तैयारियों की समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश

जयन्त प्रतिनिधि।

चमोली : जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को गैरसैंण में प्रस्तावित बजट सत्र के आयोजन की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान गैरसैंण में 9 मार्च से 13 मार्च तक होने वाले बजट सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए समय से सभी तैयारियों को पूर्ण करने की बात कही।

बैठक में सत्र आयोजन से संबंधित विभिन्न व्यवस्थाओं सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, आवास, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य सेवाएं, साफ-सफाई, संचार व्यवस्था एवं अन्य आवश्यक विभागीय तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि विधानसभा सत्र के सफल आयोजन हेतु सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विभागीय समन्वय के साथ कार्य करने की बात कही। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नियमित निरीक्षण करते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण की जाए, ताकि बजट सत्र का आयोजन सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से सम्पन्न हो सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी, परियोजना निदेशक आनंद सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में संत सम्मेलन में किया प्रतिभाग

हरिद्वार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार स्थित सप्तऋषि आश्रम मैदान (भारत माता मंदिर के समीप, सप्त सरोवर मार्ग) में आयोजित ह्यसंत सम्मेलनह्न में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सनातन चेतना के जीवंत प्रतीक आप सभी संत–महात्मा, धर्मगुरु एवं श्रद्धालुजन, माँ गंगा के पावन तट पर स्थित सप्तऋषि क्षेत्र में एकत्र होकर राष्ट्र और संस्कृति के लिए अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन महापुरुषों ने अपना सम्पूर्ण जीवन राष्ट्रधर्म, सेवा, त्याग और करुणा के लिए समर्पित किया, वे केवल संन्यासी नहीं बल्कि राष्ट्र चेतना से जुड़े दिव्य संत थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्यमित्रानंद गिरी महाराजने आध्यात्मिक ज्ञान को सामाजिक सेवा से जोड़ते हुए ऐसा जीवन दर्शन प्रस्तुत किया, जिससे अनगिनत लोगों को सेवा और मानवता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिली। उन्होंने भारत माता मंदिर की स्थापना कर सनातन संस्कृति और परंपराओं के संरक्षण का कार्य किया, जो आज भी श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का केन्द्र बना हुआ है। वर्ष 1998 के कुंभ मेले में उन्हें आचार्य महामंडलेश्वर बनाया गया, जिसके बाद अब तक 10 लाख से अधिक नागा साधुओं को दीक्षा प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सत्यमित्रानंद गिरी महाराज की मूर्ति स्थापना नई पीढ़ी के लिए आध्यात्मिक जागरण का माध्यम बनेगी। संत परंपरा किसी एक पंथ या संप्रदाय तक सीमित न होकर वसुधैव कुटुंबकम के भाव से सम्पूर्ण विश्व को जोड़ने का कार्य करती है।

सनातन धर्म मानव निर्मित नहीं, बल्कि शाश्वत सिद्धांतों पर आधारित है, जो समय के साथ चलता है और कभी पराजित नहीं होता। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने धर्मांतरण विरोधी कानून, सख्त दंगारोधी कानून, तथा लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी जिहादी मानसिकताओं के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर सभी नागरिकों के लिए समान कानून की स्थापना की गई है। युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 28 हजार से अधिक युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में सांस्कृतिक उत्थान का नया युग प्रारंभ हुआ है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर का निर्माण तथा बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान जैसे कार्य भारत को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि हरिद्वार में गंगा तट पर स्थित भारत माता मंदिर देश की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि 2027 के कुंभ मेले की तैयारियाँ की जा रही हैं और महाराज जी का जीवन निरंतर सद्कर्म और साधना से प्रेरित रहा। जम्मू–कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि भारत में बीते वर्षों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है और आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उन्होंने कहा कि जल, थल और वायु मार्गों का तीव्र विकास हुआ है तथा युवा शक्ति देश को विकसित राष्ट्र की ओर अग्रसर कर रही है। संत समाज भारतीय संस्कृति को सुदृढ़ करने और देश को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहा है। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि संतों का सान्निध्य जीवन के दुखों का समाधान है। भारत की पहचान सनातन संस्कृति से है।

शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ देश की आध्यात्मिक एकता के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि परमात्मा एक है, उसकी अभिव्यक्ति विभिन्न आस्थाओं के माध्यम से होती है। कार्यक्रम में जम्मू–कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम महाराज, योग गुरु बाबा रामदेव, सहित बड़ी संख्या में साधु–संत, जनप्रतिनिधि एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

राजकिशोर बिष्ट ने थाना यूकेडी का दामन

रुद्रप्रयाग : भाजपा के अगस्त्यमुनि मंडल अध्यक्ष रह चुके और लगभग 25 वर्षों तक पार्टी से जुड़े रहे राजकिशोर बिष्ट ने भाजपा से इस्तीफा देकर उक्रांद की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उक्रांद के जिला अध्यक्ष सूरत सिंह झिंक्वाण ने उन्हें सदस्यता दिलाई। इस मौके पर केंद्रीय महामंत्री देवेंद्र चमोली, डॉ. आशुतोष भंडारी, जिला महामंत्री दीप प्रकाश भट्ट एवं अजीत भंडारी ने उनका स्वागत किया। पार्टी के नेताओं ने कहा कि राजकिशोर बिष्ट का लंबा राजनीतिक अनुभव और क्षेत्र में मजबूत जनसंपर्क उक्रांद को आने वाले समय में और सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। (एजेंसी)

परिवार रजिस्टर की नकल का कार्यभार पूर्ववत करने की मांग

रुद्रप्रयाग : जिला प्रधान संगठन के सदस्यों ने आठ सूत्री मांगों के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने जिलाधिकारी प्रतीक जैन से शीघ्र विभिन्न मांगों पर कार्रवाई के लिए निर्देश देने की मांग की। ज्ञापन में प्रधान संगठन ने ब्लॉक की बैठक में पास होने वाली योजनाओं और प्रस्तावों में संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रस्तावों पर ग्राम प्रधानों की मुहर को अनिवार्य करने, केंद्र व राज्य सरकार की गांव स्तर की योजनाओं के शीलापट पर संबंधित ग्राम पंचायतों के प्रधानों का नाम अंकित होने, हर प्रधान को लेपटॉप सुविधा मुहैया कराने, प्रधानों के मानदेय में बढ़ोतरी, वीबीजीरामजी योजना में नेटवर्क के कारण दो समय की हाजिरी से निजात दिलाने समेत कई मांगें उठाईं। जिला प्रधान संगठन के अध्यक्ष विजयपाल जगवाण ने कहा कि मनरेगा के तहत पूर्व में किए गए विकास कार्यों के मेटेरियल पार्ट का भुगतान नहीं किया गया है। इस कारण नए कार्यों को करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं जखोली ब्लॉक प्रधान संगठन के अध्यक्ष अजय पुंडीर ने परिवार रजिस्टर की नकल का कार्यभार प्रधान के पास पूर्ववत करने की मांग उठाई। (एजेंसी)

शिविर में 80 ग्रामीणों ने कराई जांच

चमोली : ग्राफिक एरा अस्पताल की ओर से नगर पालिका के पलेठी, बधाणी और रिठोली गांव में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 80 ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। साथ ही निःशुल्क दवाएं भी दी गईं। पूर्व सैनिक संजय लखेड़ा ने बताया कि शिविर में ग्रामीणों के शुगर, हिमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, केएफटी आदि की जांच भी की गई। इस मौके पर डॉ. शिवम त्यागी, फार्मासिस्ट अमित रावत, लैब तकनीशियन सचिन पांडे, कोऑर्डिनेटर अंकित बिष्ट आदि मौजूद रहे। (एजेंसी)

जौनपुर के रेंज कार्यालय नरेंद्रनगर वन प्रभाग में करें शामिल

नई टिहरी। वन विभाग के पुनर्गठन कर मसूरी वन प्रभाग और जौनपुर ब्लॉक में स्थित रेंज कार्यालयों को नरेंद्रनगर वन प्रभाग में शामिल करने पर क्षेत्र के लोगों ने कड़ा विरोध जताया है। क्षेत्र के लोगों ने डीएम को भेजे ज्ञापन में कहा कि जौनपुर ब्लॉक में स्थित सभी रेंज कार्यालय शिफ्ट करने से क्षेत्र के लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने इस मामले में शीघ्र ही वन मंत्री से मुलाकात करने का निर्णय लिया है। नैनगांव के प्रधान विक्रम सिंह चौहान, श्रीकोट के प्रधान दीपेंद्र सिंह बिष्ट, खैराड़ के प्रधान प्रदीप कवि, शरण सिंह पंवार और गंभीर सिंह रावत आदि ने कहा कि जौनपुर ब्लॉक में स्थित बद्रीगाड रेंज, कैंपटी रेंज, देवलसारी रेंज और जौनपुर रेंज को नरेंद्रनगर वन प्रभाग में शामिल करना कतई न्यायोचित नहीं है। उन्होंने कहा कि मांग नहीं मानी गई तो क्षेत्र के लोगों को आंदोलन शुरू करने को मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में शीघ्र ही एक प्रतिनिधिमंडल वन मंत्री सुबोध उनियाल से भी मिलेगा।

वन को आग से बचाना है मानव फर्ज निभाना है

नई टिहरी। जंगलों को आग से बचाने के लिए द हंस फाउंडेशन और वन विभाग ने छात्र-छात्राओं के सहयोग से जन जागरुकता रैली निकाली गई। जीआईसी थापला ओण और जूनियर हाईस्कूल वरुणा वैली एकेडमी जखवालगांव के छात्र-छात्राओं ने जखवालगांव बाजार में रैली निकालते हुए जंगल को आग से बचाने की अपील की। इस दौरान छात्रों ने वन को आग से बचाना है मानव फर्ज निभाना है। उन्होंने जंगलों में आग लगने से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया।

जयन्त
संस्थापक
स्व.नरेन्द्र उनियाल
प्रकाशक,मुद्रक और स्वामी
नागेन्द्र उनियाल द्वारा प्रतिभा प्रेस से मुद्रित तथा बद्रीनाथ मार्ग कोटद्वार (गढ़वाल) से प्रकाशित
–सम्पादक
नागेन्द्र उनियाल
आर.एन.आई. 35469/79
फोन/फैक्स 01382–222383
मो. 8445596074, 9412081969
e-mail: nagendra.uniyal@gmail.com